

नजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम०. 14



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राजपत्रासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 1 दिसम्बर, 1986/10 अग्रहायण, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-4, the 26th November, 1986

No. 1-51/86-VS.—In pursuance to rule 135 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973 The Himachal Pradesh Universities of

Agriculture, Horticulture and Forestry Bill, 1986 (Bill No. 21 of 1986) having been introduced on the 26th November, 1986, in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is hereby published in the Gazette.

V. VERMA,
Secretary.

1986 का विधेयक संख्यांक 21

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 1986

(विधान सभा में यथा पुरः स्थापित)

हिमाचल प्रदेश के दोनों विश्वविद्यालयों, अर्थात् हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हर्टिकल्चर एण्ड फारेस्ट्री, सोलन में कृषि, औद्यानिकी और वानिकी के क्षेत्रों में अध्यापन, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के एकरूपात्मक स्तरों को प्रवर्तित करने और उपर्युक्त विश्वविद्यालयों की वित्तीय व्यवस्था और कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में एकरूपता लाने के लिए भी, उचित उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “विद्या परिषद्” से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है ;
- (ख) “अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 अभिप्रेत है ;
- (ग) “कृषि” से भूमि और जल व्यवस्था का आधारी और सहबद्ध विज्ञान, फसल उत्पादन, गृह विज्ञान, खाद्य विज्ञान, कृषि इंजीनियरी और प्रोद्योगिकी, पशुचिकित्सा और दुग्धधार विज्ञान सहित पशुपालन, मत्स्य पालन, मशरूम उगाना, मधुमक्खी पालन, चाय उगाना, रेशम कीट पालन, सब्जी उत्पादन, सामाजिक विज्ञान और कृषि विपणन, प्रसंस्करण, सहकारिता, भूमि उपयोग और व्यवस्था और ग्रामीण लोगों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान अभिप्रेत है ;
- (घ) “प्राधिकरण” से इस अधिनियम की धारा 10 में यथा विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है ;
- (ङ) “बोर्ड” से धारा 12 के अधीन यथा गठित विश्वविद्यालय का प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (च) “पाठ्य बोर्ड” से अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (छ) “कुलाधिपति” से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है ;
- (ज) “महाविद्यालय” से बोर्ड के सीधे नियन्त्रण और प्रबन्ध के अधीन विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय अभिप्रेत है चाहे वह मुख्यालय में, कैम्पस में, या अन्यत्र स्थित हो ;

संक्षिप्त
नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ।

परिभाषाएं

- (ज) "शिक्षा और अनुसंधान परिषद्" से अधिनियम की धारा 9 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी और वानिकी शिक्षा और अनुसंधान परिषद् अभिप्रेत है ;
- (ञ) "संकायाध्यक्ष" से महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (ट) "विद्यमान विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ;
- (ठ) "प्रसार" से कृषि, औद्योगिकी और वानिकी की उन्नत प्रथाओं सम्बन्धी और फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी और विपणन सहित कृषि औद्योगिकी और वानिकी सम्बन्धी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न फेजों में लगे फलो-धानियों, कृषकों और अन्य समूहों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित शिक्षा कार्यकलाप अभिप्रेत है ;
- (ड) "संकाय" से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के विभाग के शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार के कर्मचारिवृन्द अभिप्रेत हैं जिनके अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द के सभी ऐसे सदस्य हैं जो सहायक-आचार्य और उसके ऊपर के रैंक के हैं ;
- (ढ) "वानिकी" से वन वर्धन, पादप प्रजनन, फार्म वानिकी, जीव क्षेत्र पारिस्थितिकी के संरक्षण, वन्य जीवन, रेशम कीट पालन, औषधि और सुरभि पौधों और उनके उत्पादकों से सम्बन्धित आधारी और सहबद्ध विज्ञान अभिप्रेत है ;
- (ण) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार अभिप्रेत है ;
- (त) "राज्यपाल" से हिमाचल प्रदेश राज्य का राज्यपाल अभिप्रेत है ;
- (थ) "औद्योगिकी" से फलों, सब्जियों, पुष्प उत्पादन, रोपण, फसलें, मसालों और हाप्स का आधारी और सहबद्ध विज्ञान अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मशरूम उगाना, भूदृश्य, मधुमक्खी पालन और औद्योगिकी उत्पादन का विपणन और प्रसंस्करण है ;
- (द) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय के छात्रों का निवास स्थान अभिप्रेत है जो किसी महाविद्यालय के भाग के रूप में या पृथकतः विश्वविद्यालय द्वारा अनु-रक्षित या मान्यता प्राप्त है ;
- (ध) "अधिकारी" से अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (न) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;
- (प) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों और विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (फ) "विनियम" से अधिनियम की धारा 10 में यथा विनिर्दिष्ट या विनिर्दिष्ट समझे गए प्राधिकरणों के प्रवर्तन और कार्यकरण के लिए स्थापित नियम और प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत विद्या परिषद् द्वारा विश्व-विद्यालय के शैक्षणिक स्तर की स्थापना और अनुरक्षण के सम्बन्ध में बनाए गए उपबन्ध और विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकरण द्वारा विद्या-धियों, कर्मचारिवृन्द और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों के आचरण के लिए और विश्वविद्यालय के नेमी कारबार के संचालन के लिए बनाए गए उपबन्ध हो सकेंगे और इसके अन्तर्गत कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हो सकेंगे ;
- (ब) "अनुसूचित जाति" से संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 की अनु-सूची के भाग 6 में विनिर्दिष्ट और/या सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति अभिप्रेत है ;

- (भ) "अनुसूचित जन जाति" से संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 5 में विनिर्दिष्ट और/या सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जन जाति अभिप्रेत है ;
- (म) "परिनियम" से अधिनियम की धारा 53 में यथा उपवर्णित, नीति और प्रक्रिया को शासित करने वाले विश्वविद्यालय के परिनियम अभिप्रेत है ;
- (य) "विद्यार्थी" से सम्यक रूप में संस्थित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य प्रैक्षिक विशिष्टताओं के लिए विश्वविद्यालय में अध्ययन-पाठ्यक्रम लेने के लिए विश्वविद्यालय में अभ्यावेशित व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (र) "अध्यापक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 39 के अधीन शिक्षा देने और/या अनुसंधान संचालित करने और उसमें मार्गदर्शन करने और/या विस्तार प्रोग्राम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकेगा जो परिनियमों द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो बोर्ड द्वारा विहित की जाएं, अध्यापक के रूप में घोषित किया जाए ;
- (ल) "विश्वविद्यालय" से हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और/या इस अधिनियम के अधीन यथा निगमित या निगमित समझी गई डाक्टर यशवत सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हर्टिकल्चर ऐण्ड फार्स्ट्री, सोलन अभिप्रेत है ;
- (व) "कुलपति" से इस अधिनियम की धारा 24 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है ।

3. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट विद्यमान विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में, तत्स्थानी विश्वविद्यालय उसी नाम से जो शाश्वत उत्तराधिकारों और सामान्य मुद्रा सहित, इस अधिनियम के अधीन उत्तरवर्ती निगमित निकाय के रूप में निगमित किए जाएंगे या निगमित किए गए समझे जाएंगे और उसी नाम से वाद लाएंगे या उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

विश्वविद्यालयों का निगमन ।

(2) जब तक इस अधिनियम के अधीन तत्स्थानी प्राधिकरण गठित नहीं किए जाते, प्रत्येक विद्यमान विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद् और अन्य प्राधिकरणों के सदस्य, इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के तत्स्थानी प्राधिकरणों के, ऐसे सदस्यों के रूप में नियुक्त, निर्वाचित, नामनिर्देशित या निगमित समझे जाएंगे और इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन मास की समाप्ति पर या उस दिन, जिसको इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के तत्स्थानी प्राधिकरणों का गठन किया जाए, जो भी पूर्वतर हो, ऐसे सदस्यों के रूप में नहीं रहेंगे ।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल उपबन्धों के होते हुए भी, विद्यमान विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलपति और अन्य अधिकारी इस अधिनियम के अधीन निगमित विश्वविद्यालयों के अधीन अपने-अपने सम्बन्धित पदों पर बने रहेंगे ।

(4) प्रत्येक विश्वविद्यालय स्थावर और जंगम दोनों प्रकार की सम्पत्ति को क्रय, पट्टे और विनियम द्वारा या अन्यथा अर्जित और धारण करने के लिए और किसी ऐसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उस में निहित है या जो निहित हो गई है या उसके द्वारा अर्जित की गई हो, को पट्टे, विक्रय द्वारा या अन्यथा अन्तरित करने या निपटाने के लिए और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी निगमित निकाय से धन उधार लेने के लिए और संविदा करने के लिए और

इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी बातें करने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना विश्वविद्यालय की कोई भी स्थावर सम्पत्ति प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विक्रय, पट्टा, अभिघृति, बन्धक और दान द्वारा अन्तर्गत नहीं की जाएगी और न ही उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अधिम लिया जाएगा।

(5) इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (3) में, प्रत्येक विश्वविद्यालय के सामने विनिर्दिष्ट स्थान, विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा।

अधिका-
रिता।

4. (1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगा और कृषि, औद्योगिकी और वानिकी के क्षेत्र में अध्यापन, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा सम्बन्धी शक्तियाँ प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (4) में उपदर्शित परिमाण तक प्रयोक्तव्य होंगी।

(2) विश्वविद्यालय राज्य के विभिन्न भागों में, जैसा अपेक्षित हो, प्रशिक्षण केन्द्रों, अनुसंधान और प्रायोगिकी स्टेशनों के अनुरक्षण के लिए और उनमें क्षेत्रीय प्रसार कर्मचारों के प्रशिक्षण के प्रोग्राम के लिए और पालिटेक्निक की स्थापना, विकास और प्रवर्तन के लिए सम्बन्धित क्षेत्र में उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकेगा।

(3) प्रत्येक विश्वविद्यालय की अधिकारिता और प्राधिकारिता के अधीन आने वाले सभी महाविद्यालय अनुसंधान और प्रायोगिकी स्टेशन और अन्य संस्थाएँ उस विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के पूर्ण प्रबन्ध और नियन्त्रण के अधीन विश्वविद्यालय की संघटक यूनिट होंगी। किसी भी यूनिट को सम्बद्ध यूनिट के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य के भीतर स्थित और इस अधिनियम के अधीन निगमित विश्वविद्यालय से अन्य विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली कोई ऐसी शैक्षणिक संस्था जो स्नातक उपाधि और उसके ऊपर क लिए इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (4) द्वारा समनुदेशित क्षेत्र में प्रशिक्षण देती है, भारत में विधि द्वारा निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी भी रूप में सहबद्ध नहीं होगी या उसको कोई विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे, और उस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व राज्य के भीतर किसी शैक्षणिक संस्था को किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त ऐसे विशेषाधिकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर प्रत्याहृत कर लिए गए समझे जाएंगे।

(5) विश्वविद्यालय बहुशाखा शिक्षा दृष्टिकोण रखने वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय, केन्द्रीय और राज्य संस्थाओं के साथ अनुसंधान परियोजनाओं में सहयोग कर सकेगा।

उद्देश्य।

5. विश्वविद्यालय इस अनुसूची के स्तम्भ (4) में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में निम्न-लिखित प्रयोजनों के लिए स्थापित और निगमित समझा जाएगा, अर्थात् :-

- (1) कृषि, औद्योगिकी, वानिकी और विद्या और विद्वेता की अन्य सहबद्ध शाखाओं में शिक्षा देने के लिए, जिन्हें विश्वविद्यालय सम्मिलित करना आवश्यक समझे ;
- (2) आधारी और सहबद्ध दोनों प्रकार की विद्या और, अनुसंधान संचालन की अभिवृद्धि को अग्रसर करने ; और
- (3) विशेषतः ग्रामीण जनता में ऐसे विज्ञान के प्रसार का उत्तरदायित्व लेने; और

(4) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो विश्वविद्यालय, समय-समय, पर अवधारित करे।

6. (1) विश्वविद्यालय इस अधिनियम और परिणियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा :

विश्वविद्या-
लय में
प्रवेश।

परन्तु इस धारा की कोई बात—

(क) विश्वविद्यालय से किसी पाठ्यक्रम के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश देने की अपेक्षा नहीं करेगी जो विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विहित शिक्षा का मापदण्ड पूरा नहीं करता है या ऐसे किसी व्यक्ति को इसकी नामावली में बनाए रखने की अपेक्षा नहीं करेगी जिसका शैक्षणिक अभिलेख कोई उपाधि प्रदान करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मापदण्ड के नीचे हो या जिसका व्यक्तिगत आचरण ऐसा हो जिससे विश्वविद्यालय के प्रयोजनों पर या अन्य छात्रों और कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय से किसी पाठ्यक्रम के लिए उस संख्या से अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश देने की अपेक्षा नहीं करेगी जिन्हें विश्वविद्यालय के शैक्षिक, अनुसंधान और प्रसार कार्यक्रमों में या ऐसे किसी विशिष्ट महाविद्यालय या विभाग में जो विधा परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, प्रवेश दिया जा सकता है।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय, इसके बोर्ड के विनिर्दिष्ट विनिश्चय के अनुसार महाविद्यालयों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के वर्ग के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करेगा किन्तु ऐसा कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे अभ्यर्थी की बात विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित प्रवेश के मापदण्ड को पूरा नहीं करता है।

7. विश्वविद्यालय के इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (4) में इसके समक्ष उपद्रशित क्षेत्र में, निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

विश्वविद्या-
लय की
शक्तियाँ
और कृत्य।

- (1) प्रसार शिक्षा प्रोग्राम के माध्यम से शिक्षा, अनुसंधान संचालन, अनुसंधान के परिणामों के प्रसार और तकनीकी जानकारी के लिए उपबन्ध करना;
- (2) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को संस्थित करना;
- (3) पाठ्यक्रम संस्थित करना और परीक्षाएं लेना और ऐसे व्यक्ति को जो:-

(क) यथा विहित पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है, या

(ख) विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त संस्था में उन शर्तों के अधीन जो विहित की जाएँ, अनुसंधान करता है;

उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना;

- (4) सम्मानिक उपाधियाँ और अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना, जो विहित की जाएँ;

- (5) क्षेत्रीय कर्मचारियों, फेलोशिपियों, कृषकों और अन्य व्यक्तियों के लिए, जो विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों के रूप में नामावलीगत न हों, व्याख्यानों और शिक्षण का उपबन्ध करना और उनको ऐसे प्रमाणपत्र देना जो विहित किए जाएं ;
- (6) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करें, इस अधिनियम की धारा 4 में उपबन्धित परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, सहकार करना ;
- (7) इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (4) में इसके समक्ष उपदर्शित क्षेत्रों के सम्बन्ध में महा-विद्यालयों का अनुरक्षण करना ;
- (8) इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (4) में इसके समक्ष उपदर्शित क्षेत्रों में अध्यापन, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के लिए प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, अनुसंधान स्टेशनों और संस्थाओं का अनुरक्षण करना ;
- (9) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्तियां करना ;
- (10) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ;
- (11) परिनियमों के अनुसार, अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और देना ;
- (12) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारिवृन्द के लिए निवास सुविधा संस्थित और अनुरक्षित करना ;
- (13) ऐसी फीसों और अन्य प्रभार, जो विहित किए जाएं, नियत करना, मांगना और प्राप्त करना ;
- (14) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, आचरण और अनुशासन का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करना और उनके स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना ;
- (15) अध्यापकों की अर्हताएं अवधारित करना और इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (4) में इसके समक्ष उपदर्शित क्षेत्र में, महाविद्यालय में शिक्षा देने या अनुसंधान और प्रसार शिक्षा निष्पादित करने के लिए अर्हित व्यक्ति को मान्यता देना ;
- (16) ऐसे सभी अन्य कार्य या बातें करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों, चाहे पूर्वोक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों, या नहीं ।

परिदर्शन
और
निरीक्षण ।

8. (1) कुलाधिपति को, किसी ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कर्मशालाओं और उपस्करों और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या प्रशासित किसी संस्था, महाविद्यालय या छात्रावास और विश्वविद्यालय या इसके निर्देशन के अधीन संचालित अध्यापन कार्य या अन्य कार्य और विश्वविद्यालय के किसी अन्य कृत्य के संचालन का निरीक्षण कराने का और उसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार होगा ।

(2) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण या जांच करने के अपने आशय की सम्यक सूचना विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित होन और सुन जाने का अधिकार होगा ।

(3) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम विश्वविद्यालय को संसूचित करेगा और उन पर इसकी राय जानने के पश्चात् विश्वविद्यालय को, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सलाह देगा और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत करेगा।

(4) विश्वविद्यालय इस प्रकार नियत समय के भीतर कुलाधिपति को, कुलाधिपति द्वारा दी गई सलाह पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई की रिपोर्ट देगा।

(5) जहां विश्वविद्यालय ने नियत समय सीमा के भीतर कुलाधिपति के समाधान-प्रद रूप में कार्रवाई नहीं की है, वहां कुलाधिपति विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी करेगा जो वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(6) इस धारा की पूर्वगामी उप-धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी समय कुलाधिपति की यह राय हो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलाप विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अप्रसर करने में या अधिनियम और कानूनी विनियमों के उल्लंघनों या विश्वविद्यालय के अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान या प्रसार के स्तर को बनाए रखने के लिए वांछनीय विशेष उपायों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं तो वह विश्वविद्यालय को किसी ऐसे मामले को उपदर्शित कर सकेगा जिस के सम्बन्ध में वह स्पष्टीकरण चाहता हो और विश्वविद्यालय से, ऐसे समय के भीतर जो कुलाधिपति निर्दिष्ट करे, स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि विश्वविद्यालय निर्दिष्ट समय के भीतर स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है या ऐसा स्पष्टीकरण देता है जो कुलाधिपति की राय में असमाधानप्रद है तो कुलाधिपति ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो मामले की परिस्थितियों में, उसे आवश्यक और वांछनीय प्रतीत हों और ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो वह इन निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक समझे।

(7) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रशासन के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी देगा जैसी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षित हो।

9. (1) इस राज्य में इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों के कार्य-कलापों के प्रभावकारी समन्वयन, विशेषतः अध्यापन, अनुसंधान, प्रसार, शिक्षा और सामान्य हित के अन्य मामलों और विश्वविद्यालयों के कृत्यों के पाक्षिक मूल्यांकन और उनके शैक्षणिक वित्तीय कार्यकलापों और कार्यक्रमों के अधीक्षण के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, शिक्षा और अनुसंधान परिषद् का गठन करेगी जो "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी और वानिकी शिक्षा और अनुसंधान परिषद् कहलाएगी"।

राज्य शिक्षा और अनुसंधान परिषद् का गठन और इसकी शक्तियाँ और कर्तव्य।

(2) राज्य सरकार का मुख्य सचिव, परिषद् का अध्यक्ष होगा और परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(i) राज्य सरकार के कृषि उत्पादन आयुक्त ;

(ii) विश्वविद्यालयों के कुलपति ;

(iii) राज्य सरकार के कृषि, औद्योगिकी, पशुपालन, वित्त और वन विभागों के सचिव; और

(iv) भारतीय कृषि अनुसंधान, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि।

(3) उप-धारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शिक्षा और अनुसंधान परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :-

- (क) राजकोष से अनुदान या ऋण द्वारा वित्तपोषित, नए पाठ्यक्रमों या विद्या शाखाओं, विभागों, स्कीमों या परियोजनाओं को चलाने के लिए विश्वविद्यालय को अनुमति प्रदान करना ;
- (ख) विश्वविद्यालयों में प्रभावकारी समन्वयन स्थापित करने और उन्हें समुचित मार्गदर्शन और निर्देश देने के उद्देश्य से कृषि, औद्योगिकी और वानिकी में शिक्षा, अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के सम्बन्ध में समय-समय पर विश्वविद्यालयों में किए गए कार्य का पुनर्विलोकन करना ;
- (ग) राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों सम्बन्धी उन कार्यकलापों पर सलाह देना जो राज्य सरकार द्वारा इसे निर्दिष्ट किए जाएं ;
- (घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए आनुषंगिक और अपेक्षणीय हैं ;
- (ङ) एक विश्वविद्यालय से दूसरे में अनुसंधान या प्रायोगिक केन्द्रों के अन्तरण या विभाजन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना ।

(4) शिक्षा और अनुसंधान परिषद् को अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में, कुलाधिपति को सूचित करते हुए, विश्वविद्यालयों को आवश्यक निर्देश देने की शक्ति होगी जो अन्तिम और विश्वविद्यालयों पर आबद्धकर होंगे और यह सुनिश्चित करना सम्बन्धित कुलपति का कर्तव्य होगा कि ऐसे निर्देशों को तत्परता और उचित रूप में कार्यान्वित किया जाए और इस प्रयोजन के लिए कुलपति को इस अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (5) में यथा उपबन्धित सभी आवश्यक शक्तियाँ होंगी और वह उनका प्रयोग करेगा ।

(5) शिक्षा और अनुसंधान परिषद् अपने कारबार के संचालन में ऐसी प्रक्रिया अवधारित करेगी जैसी वह उचित समझे ।

(6) शिक्षा और अनुसंधान परिषद् को उसकी सदस्यता में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के होते हुए भी, कार्य करने की शक्ति होगी ।

प्राधिकरण ।

10. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :-

- (i) सिनेट ;
- (ii) प्रबन्ध बोर्ड ;
- (iii) विद्या परिषद् ;
- (iv) प्रसार परिषद् ;
- (v) अनुसंधान परिषद् ;
- (vi) पाठ्य बोर्ड ;
- (vii) वित्त समिति ; और
- (viii) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य निकाय जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं ।

11. (1) सिनेट, निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी :-

सिनेट ।

(अ) हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय

पदेन सदस्य :

- (i) कुलाधिपति ;
- (ii) कुलपति ;
- (iii) सरकार का कृषि उत्पादन आयुक्त ;
- (iv) सरकार का सचिव (कृषि) ;
- (v) सरकार का सचिव (पशुपालन) ;
- (vi) सरकार के कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन विभागों के विभागाध्यक्ष ;
- (vii) विश्वविद्यालय के सभी संकायाध्यक्ष, निदेशक और अन्य वैधानिक अधिकारी ।

अन्य सदस्य :

- (viii) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा और में से ऐसी रीति में निर्वाचित दो सदस्य, जो विधान सभा अध्यक्ष द्वारा विहित की जाए ;
- (ix) विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संकायाध्यक्षों, निदेशकों से अन्यथा परिनियमों द्वारा विहित रीति में निर्वाचित विश्वविद्यालय के दो शिक्षक/विभागाध्यक्ष, जिनका 5 वर्ष का शैक्षिक अनुभव हो ;
- (x) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों (शिक्षकों से अन्यथा) का, परिनियमों में विहित रीति से निर्वाचित एक सदस्य ।

(आ) डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हाटिकलचर एण्ड फारेंस्ट्री,
सोलन

पदेन सदस्य :

- (i) कुलाधिपति ;
- (ii) कुलपति ;
- (iii) सरकार का कृषि उत्पादन आयुक्त ;
- (iv) सरकार का सचिव (औद्योगिकी) ;
- (v) सरकार का सचिव (वन) ;
- (vi) सरकार के कृषि, औद्योगिकी और वन विभागों के विभागाध्यक्ष ;
- (vii) विश्वविद्यालय के सभी संकायाध्यक्ष, निदेशक और अन्य वैधानिक अधिकारी ।

अन्य सदस्य :

- (viii) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा और में से ऐसी रीति में निर्वाचित दो सदस्य, जो विधान सभा अध्यक्ष द्वारा विहित की जाए ;
- (ix) विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, संकायाध्यक्षों, निदेशकों से अन्यथा परिनियमों द्वारा विहित रीति में निर्वाचित विश्वविद्यालयों के दो शिक्षक/विभागाध्यक्ष, जिनका 5 वर्ष का शैक्षिक अनुभव हो ;
- (x) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों (शिक्षकों से अन्यथा) का, परिनियमों में विहित रीति से निर्वाचित एक सदस्य ।

- (2) सिनेट के पदेन सदस्यों से अन्यथा, सदस्यों की पदावधि, उनके अपने-अपने निर्वाचन की तारीख से दो वर्ष के लिए होगी और कोई अगली अवधि, जो उक्त दो वर्ष की अवधि की समाप्ति और, यथास्थिति, आगामी उत्तरवर्ती निर्वाचन या नामनिर्देशन, जो आह्वानिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन या नामनिर्देशन नहीं है, के बीच पड़ती है, इसके अन्तर्गत है।
- (3) सिनेट, कुलाधिपति द्वारा नियत की जाने वाली तारीखों को, कलेंडर वर्ष में एक बार बैठक करेगी जिसे सिनेट की वार्षिक बैठक कहा जाएगा।
- (4) कुलाधिपति, जब वह उचित समझे, और सिनेट के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में अध्यक्षता करने पर सिनेट की विशेष बैठक बुलाएगा।
- (5) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सिनेट,—
 - (i) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और प्रोग्रामों का पुनर्विलोकन करेगी और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपायों का सुझाव देगी ;
 - (ii) विश्वविद्यालयों की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं, वित्तीय प्राकरूलनों और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करेगी, और प्रस्ताव पारित करेगी; और
 - (iii) कुलाधिपति को ऐसे विषय पर सलाह देगी जो सलाह के लिए इसे निर्दिष्ट किया जाए।

प्रबन्ध बोर्ड।

12. (1) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के लिए प्रबन्ध बोर्ड का गठन करेगा और बोर्ड निम्नलिखित से गठित होगा :—

(अ) हिमाचल प्रदेश कृषि विद्यालय

पदेन सदस्य :

- (i) कुलपति;
- (ii) डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चर ऐण्ड फारेस्ट्री सोलन का कुलपति ;
- (iii) सरकार का कृषि उत्पादन आयुक्त;
- (iv) सरकार का सचिव (कृषि)
- (v) सरकार का सचिव (पशुपालन) ;
- (vi) सरकार का सचिव (वित्त) ;
- (vii) सरकार के कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभागों के विभागाध्यक्ष ;

अन्य सदस्य :

- (viii) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों/निदेशकों में से एक अधिकारी जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;
- (ix) दो प्रमुख वैज्ञानिक, एक कृषि और दूसरा पशुपालन विज्ञान में, जिनकी अनुसंधान और शिक्षा की पृष्ठ भूमि होगी जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

- (X) दो उन्नत कृषक, किसान या पशुपालक जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;
- (xi) राज्य के जनजातीय क्षेत्र का एक उन्नत कृषक। या पशुपालक जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;
- (xii) एक उत्कृष्ट महिला समाज सेविका, अधिमानतः जिसकी ग्रामीण उन्नति की पृष्ठ भूमिका हो, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाएगी ;
- (xiii) एक विख्यात उद्योगपति या निर्माता जिसको कृषि विकास का विशेष ज्ञान हो, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ?
- (xiv) एक प्रख्यात इन्जीनियर जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;
- (xv) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से एक प्रतिनिधि; और
- (xvi) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् देहरादून, (स्थापित की जाएगी) का एक प्रतिनिधि ।

(आ) डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हाबिकल्चर ऐण्ड फारेस्ट्री सोलन पदेन सदस्य :

- (i) कुलपति ;
- (ii) हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति ;
- (iii) सरकार का कृषि उत्पादन आयुक्त ;
- (iv) सरकार का सचिव (श्रौद्यानिकी) ;
- (v) सरकार का सचिव (वित्त) ;
- (vi) सरकार का सचिव (वन) ;
- (vii) सरकार के उद्यान, वन और कृषि विभागों के विभागाध्यक्ष ;

अन्य सदस्य:

- (viii) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों/निदेशकों में से एक अधिकारी, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;
- (ix) दो प्रमुख वैज्ञानिक, एक श्रौद्यानिकी में और दूसरा वानिकी में जो कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे ;
- (x) दो उन्नत फलोद्यानी या कृषक, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;
- (xi) राज्य के जनजातीय क्षेत्र का एक उन्नत फलोद्यानी या कृषक जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;
- (xii) एक उत्कृष्ट महिला समाज सेविका, अधिमानतः जिसकी ग्रामीण उन्नति की पृष्ठ भूमिका हो जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाएगी ।
- (xiii) एक प्रख्यात इन्जीनियर, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;
- (xiv) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि और ;
- (xv) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् देहरादून (स्थापित की जाएगी) का एक प्रतिनिधि ।

- (2) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय बोर्ड का गैर-सदस्य सचिव होगा ।
- (3) पदेन सदस्यों के सिवाए बोर्ड के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी ।
- (4) बोर्ड का सदस्य, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को सम्बोधित लिखित नोटिस द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

- (5) यदि किसी कारण बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों के पद में रिक्ति होती है तो वह इस धारा के उपबन्धों के अनुसार उस पर किसी अन्य व्यक्ति को, यथास्थिति, नियुक्त या नाम निर्दिष्ट करके, भरी जा सकेगी।
- (6) बोर्ड की बैठक में, बोर्ड के आठ सदस्यों से गणपूर्ति होगी।
- (7) कुलपति, बोर्ड का अध्यक्ष होगा।
- (8) बोर्ड के सदस्य, ऐसे बैंकिंग और यात्रा भत्ते के सिवाए, जो विहित किया जाए, इस अधिनियम के अधीन ऐसे सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के पालन के लिए कोई पारिभ्रमिक प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

बोर्ड की
शक्तियाँ
और कृत्य।

13. (1) बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और पालन करेगा, अर्थात्:-
 - (क) विश्वविद्यालय की वित्तीय अपेक्षताओं और प्राक्कलनों का पुनर्विलोकन करना और विचार करना और उसके बजट को अनुमोदित करना;
 - (ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पदों पर नियुक्ति करना;
 - (ग) आशयित प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययन पर रखे गए किसी निधि के प्रशासन के लिए उपबन्ध करना;
 - (घ) विश्वविद्यालय की निधियों के विनिधान और प्रत्याहरण की व्यवस्था करना;
 - (ङ) पूंजीगत उन्नयन के लिए धन उधार लेना और इसके प्रतिसंदाय के लिए उचित व्यवस्था करना;
 - (च) विश्वविद्यालय की ओर से सम्पत्ति को स्वीकार, अर्जित, धारण और व्ययन का उपबन्ध करना;
 - (छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के रूप और उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश देना;
 - (ज) स्थायी या अस्थायी ऐसी समितियों की नियुक्ति करना जैसी बोर्ड आवश्यक समझे और अधिनियम या परिनियमों के कार्यक्षेत्र के भीतर उनके निर्देश निबन्धन स्थापित करना;
 - (झ) इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नीतियों का अवधारण और विनियमन करना;
 - (ञ) विद्या परिषद् द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के अन्तर्गत यथा अवधारित विद्या और पाठ्यक्रमों की शाखाओं में शिक्षा, अध्यापन और प्रशिक्षण के लिए और अनुसंधान और अभिवृद्धि और ज्ञान के प्रसार के लिए, वित्तीय उपबन्ध करना;
 - (ट) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए महाविद्यालयों, छात्रावासों, प्रयोगशालाओं और प्रायोगिक फार्मों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए उपबन्ध करना;
 - (ठ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को संस्थित और प्रदान करने के लिए उपबन्ध करना;
 - (ड) छात्रवृत्तियाँ, अध्येतावृत्तियाँ, तगमें, पुरस्कार इत्यादि संस्थित, अनुरक्षित और प्रदान करने के लिए उपबन्ध करना;
 - (ढ) विश्वविद्यालय की ओर से न्यास, वसीयत और दान प्रतिगृहीत करना;

(ण) ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर और उतनी बार, जैसा आवश्यक समझा जाए, बैठक करना :

परन्तु बोर्ड की नियमित बैठक तीन मास में कम से कम एक बार की जाएगी ;

(त) अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी मामलों को विनियमित और अवधारित करना और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना और कर्तव्यों का निर्वहन करना जैसे कि अधिनियम या परिनियमों द्वारा बोर्ड को सौंपे या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

(2) बोर्ड, परामर्श के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसको विचाराधीन विषय के बारे में अनुभव या विशेष ज्ञान हो, बैठक में उपस्थित होने के लिए आमन्त्रित कर सकेगा । ऐसा व्यक्ति ऐसी बैठक में बोल सकेगा या उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले सकेगा किन्तु ऐसी किसी बैठक में मत देने का हकदार नहीं होगा । इस प्रकार आमन्त्रित कोई व्यक्ति, बैठक में उपस्थित होने के लिए, ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो बिहित किए जाएं ।

14. (1) विश्वविद्यालय के लिए एक विद्या परिषद् होगी जो अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करेगी और उपाधियों या डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों से सम्बन्धित, शिक्षण, शिक्षा और परीक्षाओं और अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं । यह कुलपति को विद्या से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के सभी मामलों पर सलाह देगी ।

विद्या
परिषद् ।

(2) विद्या परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्:—

- (i) कुलपति, जो पदेन अध्यक्ष होगा ;
- (ii) विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष ;
- (iii) विश्वविद्यालय का अनुसंधान निदेशक ;
- (iv) विश्वविद्यालय का प्रसार शिक्षा निदेशक ;
- (v) निदेशक (मानिकी शिक्षा) वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून ;
- (vi) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष ;
- (vii) विश्वविद्यालय का विद्यार्थी-कल्याण अधिकारी ;
- (viii) प्रत्येक महाविद्यालय के दो ज्येष्ठतम प्राचार्य, चक्रानुक्रम में, दो वर्ष की अवधि के लिए ;
- (ix) (क) हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, दो प्रख्यात वैज्ञानिक, एक कृषि में और दूसरा पशु विज्ञान में ;
(ख) डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चर ऐण्ड फार्स्ट्री सोलन के सम्बन्ध में, दो प्रख्यात वैज्ञानिक, एक ओधानिकी में और दूसरा बानिकी में ;
- (x) कुल सचिव, विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा ;

(3) परिषद् के सदस्यों की एक-तिहाई संख्या से गणपूति होगी ।

विद्या
परिषद् की
शक्तियां
और कृत्य ।

15. (1) विद्या परिषद् को, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी पाठ्यक्रमों को विनियमित और विहित और अवधारित करने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय में अध्यापन और अन्य शिक्षा कार्यक्रमों पर इसका सामान्य नियन्त्रण होगा और उसके स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी ।

(2) उसे अपने नियन्त्रणाधीन सभी विद्या सम्बन्धी विषयों की बाबत इस अधिनियम और परिनियमों से संगत विनियम बनाने और ऐसे विनियमों को संशोधित या निरसित करने की शक्ति होगी ।

(3) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्या परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :—

- (i) सभी विद्या सम्बन्धी विषयों पर, जिसके अन्तर्गत पुस्तकालयों का नियन्त्रण और अनुरक्षण भी है, बोर्ड को सलाह देना ;
- (ii) नए महाविद्यालयों, विभागों, प्रायोगिक स्टेशनों, उप-स्टेशनों, आचार्य पदों, सह-आचार्य पदों और अन्य अध्यापन पदों को, जिनके अन्तर्गत अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के पद भी हैं, प्रस्थापित करने के लिए और उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना ;
- (iii) अध्यापन, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के विभागों के गठन और पुनर्गठन के लिए स्कीमें बनाना, संशोधित करना और पुनरीक्षित करना ;
- (iv) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में विनियम बनाना और प्रवेश देने के लिए विद्यार्थियों की संख्या का निर्धारण करना ;
- (v) उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विनियम बनाना ;
- (vi) परीक्षाओं के संचालन और स्तर को बनाए रखने और अभिवृद्धि के लिए विनियम बनाना ;
- (vii) स्नात्कोत्तर अध्यापन, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के सम्बन्ध में सिफारिशें करना ;
- (viii) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए विहित की जाने वाली अर्हताओं के सम्बन्ध में सिफारिश करना ;
- (ix) सम्मानिक उपाधि देने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना ; और
- (x) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

प्रसार
परिषद् ।

16. (1) विश्वविद्यालय के लिए एक प्रसार परिषद् होगी ।

(2) प्रसार परिषद् का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा विहित की जायें ।

17. (1) विश्वविद्यालय के लिए एक अनुसंधान परिषद् होगी। अनुसंधान
परिषद्।
- (2) अनुसंधान परिषद् का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।
18. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक महाविद्यालय के लिए एक पाठ्य बोर्ड होगा। पाठ्य बोर्ड।
- (2) महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष सम्बन्धित पाठ्य बोर्डों के अध्यक्ष होंगे और महाविद्यालयों के विभागाध्यक्ष उसके सदस्य होंगे।
- (3) कुलपति पाठ्य बोर्ड के लिए उसी या अन्य महाविद्यालयों से सम्बन्धित विषयों या विज्ञानों के ऐसे अन्य अध्यापकों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा, जैसे वह उचित समझे।
- (4) ऐसे पाठ्य बोर्ड के कर्तव्य, अध्ययन और शिक्षा से सम्बद्ध अन्य मामलों के लिए समेकित और संतुलित पाठ्यक्रम सुनिश्चित करते हुए, पाठ्यविवरण विहित करने होंगे।
- (5) महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं और वह विभाग के उचित गठन और कामकाज के लिए महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और वह उसके विभाग को सौंपे गए क्रमशः अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के लिए अनुसंधान और प्रसार शिक्षा निदेशकों के प्रति उत्तरदायी होगा।
- (6) पाठ्य बोर्ड ऐसे कृत्यों का पालन या ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि परिनियमों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं।
19. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित से गठित एक वित्त समिति होगी:— वित्त समिति,
इसकी
शक्तियां
और कर्तव्य।
- (i) कुलपति, जो समिति का पदेन अध्यक्ष भी होगा ;
- (ii) सरकार का वित्त सचिव या उसका प्रतिनिधि ;
- (iii) डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चर ऐण्ड फारेस्ट्री सोलन के सम्बन्ध में कृषि और वन विभाग के विभागाध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभागों के विभागाध्यक्ष;
- (iv) अपने गैर-सरकारी सदस्यों में से बोर्ड द्वारा चुना गया एक सदस्य।
- (2) लेखा नियन्त्रक, वित्त समिति का गैर सदस्य सचिव होगा।
- (3) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—
- (i) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की परीक्षा करना और उस पर बोर्ड को सलाह देना;
- (ii) वार्षिक बजट प्राक्कलनों की परीक्षा करना और इस पर बोर्ड को सलाह देना ;
- (iii) वार्षिक लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट की और उस पर की गई कार्रवाई की परीक्षा करना ;

- (iv) समय-समय पर विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करना;
- (v) विश्वविद्यालय के वित्त से सम्बन्धित सभी मामलों पर विश्वविद्यालय को सिफारिशें करना; और
- (vi) ऐसे सभी प्रस्तावों पर, जिन में ऐसा व्यय अन्तर्वर्लित हो जिसके लिए बजट में कोई उपबन्ध न किया गया हो या जिसके लिए बजट में उपबन्धित राशि से अधिक व्यय अन्तर्वर्लित हो, बोर्ड को सिफारिशें करना।

प्राधिकरण
की सदस्यता
के सम्बन्ध
में उपबन्ध।

20. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाए यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या अन्य निकाय के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, उसकी मृत्यु, पदत्याग, हटाए जाने या अन्यथा अपनी पूर्ण पदावधि पूरी करने में असमर्थ है, तो इस प्रकार हुई रिक्ति, यथा शक्य सुविधानुसार, यथास्थिति, नियुक्ति, निर्वाचन या नाम निर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त, निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसी रिक्ति की पदावधि के उस अनुवसित भाग के लिए भरेगा जिसके लिए वह सदस्य, जिसके स्थान पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त, निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया है, अन्यथा पद पर बना रहता।

(2) कुलाधिपति, बोर्ड की सिफारिश पर, किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की सदस्यता से इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति नैतिक अधमता से अन्तर्वर्लित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है, किन्तु किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसे मुनवाई का अवसर दिए बिना हटाए जाने का आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य निकाय के, चाहे वह विश्वविद्यालय का हो या नहीं, प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य है, ऐसे प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा, यदि वह, अपनी सदस्यता की अवधि के अवसान से पूर्व, उस निकाय का सदस्य नहीं रह जाता है जिसके द्वारा वह नियुक्त या निर्वाचित किया गया था।

(4) जब कभी कोई व्यक्ति अपने द्वारा धारित पद के कारण विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य बनता है, वह तुरन्त ऐसे प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह अपनी सदस्यता की अवधि के अवसान से पूर्व ऐसे पद का धारक नहीं रह जाता:

परन्तु उसके बारे में केवल इस कारण कि वह चार महीने से अनधिक अवधि के लिए छुट्टी पर गया है यह नहीं माना जायेगा कि वह अपने पद का धारक नहीं रहा है।

(5) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के पदेन सदस्यों से भिन्न कोई सदस्य, समुचित प्राधिकरण के समक्ष रखे जाने के लिए कुल-सचिव को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(6) संकायाध्यक्ष या निदेशक से भिन्न विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी, चाहे वह वैतनिक हो या न हो, कुलपति को सम्बोधित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र उस तारीख से जिसको कि यह रिक्ति भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जाता है या कुलपति द्वारा प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान पर, जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी होगा।

कतिपय
कार्यों की
विधि-
मान्यता
और परि-
क्षा।

21. (1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं हो जाएगी कि इसके सदस्यों में कोई स्थान रिक्त है या किसी ऐसे व्यक्ति ने कार्यवाही में भाग लिया है जो तत्पश्चात् ऐसा करने का हकदार नहीं पाया जाता है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय या उसके किन्हीं प्राधिकरण द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए और पारित सभी कार्य और आदेश अन्तिम होंगे और इस अधिनियम या परिनियमों या विनियमों के अनुसरण में की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए विश्वविद्यालय या उसके प्राधिकरण के विरुद्ध कोई भी वाद संस्थित नहीं किया जाएगा या क्षति का दावा नहीं किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम या परिनियमों या विनियमों के अधीन किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही, बॉर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं होगी।

(4) विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में किसी भी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही के लिए दायी नहीं होगा यदि कार्य इस अधिनियम द्वारा या अधीन, उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निष्पादन या कृत्यों के निर्वहन में, सद्भावपूर्वक किया गया हो।

22. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी हो सकेंगे, अर्थात्:—

- (i) कुलाधिपति,
- (ii) कुलपति,
- (iii) महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष,
- (iv) अनुसंधान निदेशक,
- (v) प्रसार शिक्षा निदेशक,
- (vi) कुलसचिव,
- (vii) लेखा नियन्त्रक,
- (viii) सम्पदा अधिकारी,
- (ix) पुस्तकालयाध्यक्ष,
- (x) विद्यार्थी कल्याण अधिकारी; और
- (xi) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

विश्वविद्या-
लय क
अधिकारी।

23. (1) राज्यपाल, अपने पद के कारण विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

कुलाधिपति।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होगा और यदि उपस्थित हो तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति के पुष्टिकरण के अधीन होगा।

(4) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जैसे कि इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

24. (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा जिसे कुलाधिपति द्वारा निम्नलिखित से गठित चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाएगा:—

कुलपति।

- (i) कुलाधिपति का एक नामनिर्देशित;
- (ii) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्; और
- (iii) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उसका नामनिर्देशित।

(2) कुलाधिपति, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सदस्यों में से एक को चयन समिति का अध्यक्ष नामनिर्देशित करेगा।

(3) कुलपति, सामान्यतः पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और अन्य पांच वर्षों के लिए पुनः नियुक्ति का पात्र होगा किन्तु 65 वर्ष की आयु के पश्चात् नहीं कुलपति की परित्यक्तता और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी की विहित की जाएं और वे उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अधिकार में नहीं बदली जाएंगी:

परन्तु कुलाधिपति उसे तब तक पद पर बने रहने की अनुमति दे सकेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्ति नहीं कर दिया जाता किन्तु यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) कुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित उस द्वारा हस्ताक्षरित एक मास का नोटिस देकर, अपना पद त्याग सकेगा। कुलाधिपति, नोटिस की अवधि का अधित्याग कर सकेगा और राज्य सरकार के परामर्श से त्यागपत्र तुरन्त स्वीकार कर सकेगा।

(5) कुलाधिपति छुट्टी, बीमारी या किसी अन्य कारणवश कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, कुलपति के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्यों में से, ऐसे प्रबन्ध कर सकेगा जैसे वह उचित समझे। जहां कुलपति का पद त्यागपत्र द्वारा या अन्यथा स्थायी रूप से रिक्त हो जाए, तो रिक्ति इस धारा की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त कुलपति पूरी अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(6) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में जान बूझ कर लोप करता है या इन्कार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना, विश्वविद्यालय के हितों के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, कुलपति को उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई के लिए कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य।

25. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी और बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा। वह कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उपाधियों प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को उपाधियां प्रदत्त करेगा।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियन्त्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) कुलपति, जब तक वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को अस्थायी रूप से यह शक्ति प्रत्योजित नहीं कर देता, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् की बैठकें बुलाएगा।

(4) कुलपति इस अधिनियम, परिनियमों और विनियमों के उपबन्धों का संदभावपूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी कि इस सम्बन्ध में आवश्यक हों।

- (5) कुलपति, समय समय पर, शिक्षा और अनुसंधान परिषद् द्वारा धारा 9 के अधीन दिए गए निदेशों के तत्पर और उचित कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय और इसके प्राधिकरणों और अधिकारियों की ओर से उत्तरदायी होगा और इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए या बनाए गए समझे जाने वाले परिणियमों और विनियमों के अधीन किसी बात के होते हुए भी उसे इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ होंगी और वह उनका प्रयोग करेगा।
- (6) कुलपति वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन और वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र को बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (7) कुलपति किसी भी आपात स्थिति में, जिस में उसकी राय में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, कोई भी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे मामले में उसके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकरण को देगा जिसे सामान्यतः ऐसे मामले में कार्रवाई करनी होती और यदि वह प्राधिकरण कुलपति की कार्रवाई के साथ असहमत हो तो मामला कुलाधिपति को निदिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा :
- परन्तु इस धारा की कोई भी बात, कुलपति को ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त करने वाली नहीं मानी जाएगी जो सम्यक रूप से प्राधिकृत और बजट में उपबधित नहीं है।
- (8) पूर्ववर्ती उप-धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों, निलम्बन और पदच्युति के आदेशों को कार्यान्वित करेगा।
- (9) जहाँ कुलपति द्वारा उप-धारा (6) के अधीन की गई कोई कार्रवाई, विश्वविद्यालय में सेवारत किसी व्यक्ति के अहित में है, ऐसी कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है और जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है, वह उस तारीख से जिस तारीख को, की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना उसे दी जाती है, तीस दिन के भीतर, बोर्ड को अपील कर सकेगा।
- (10) कुलपति, विश्वविद्यालय के उचित प्रशासन और अध्यापन, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के बीच सधन, सहकार और सहयोग के लिए उत्तरदायी होगा।
- (11) कुलपति, बोर्ड को सूचित करके विश्वविद्यालय में किसी अधिकारी, अध्यापक और अन्य कर्मचारी की रिक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक अवधि के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकेगा।
- (12) कुलपति, इस अधिनियम के प्रयोजनों और उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी कि विहित की जाएं।
- (13) कुलपति, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर, परिणियमों में विहित नीति से, संकाय के सदस्यों द्वारा किए गए अध्यापन, प्रसार और अनुसंधान कार्य का निर्धारण और मूल्यांकन करेगा। ऐसे निर्धारण और मूल्यांकन पर, यदि

कुलपति की यह राय हो कि संकाय के किसी सदस्य का कार्य और आचरण संतोषप्रद नहीं है तो वह परिणियमों में अधिकथित रीति से ऐसे सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ करेगा या आरम्भ करवाएगा ।

विश्वविद्या-
लय के अन्य
अधिकारी
और उनके
सामान्य
निबन्धन
और शर्तें ।

26. (1) धारा 22 के खण्ड (iii) से (xi) तक, में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय का अधिकारी, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और वह बोर्ड द्वारा उस चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाएगा जो इस प्रयोजन के लिए परिणियमों के अधीन गठित की जाए ।

(2) ऐसे अधिकारी का वेतन और सेवा को अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि परिणियमों द्वारा विहित की जाए ।

महाविद्यालयों
के संकाया-
ध्यक्ष ।

27. (1) प्रत्येक महाविद्यालय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो उसके महाविद्यालय से सम्बन्धित सभी मामलों के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(2) संकायाध्यक्ष, उसके महाविद्यालय के विभागों के गठन और निवासी शिक्षण के संचालन के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(3) संकायाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसे कि परिणियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

अनुसंधान
निदेशक ।

28. (1) एक अनुसंधान निदेशक होगा जो इस अधिनियम की धारा 37 में यथा उपवर्णित अनुसंधान प्रोग्राम के निर्देशन और समन्वयन और अनुसंधान केन्द्रों के दक्ष कार्यकरण के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति, उत्तरदायी होगा ।

(2) अनुसंधान निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिणियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

प्रसार शिक्षा
निदेशक ।

29. (1) एक प्रसार शिक्षा निदेशक होगा जो इस अधिनियम की धारा 38 में यथा उपवर्णित सम्बन्धित क्षेत्र में प्रसार प्रोग्राम के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति, उत्तरदायी होगा ।

(2) प्रसार शिक्षा निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिणियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

कुल सचिव ।

30. (1) विश्वविद्यालय का एक कुल-सचिव होगा जो विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय के सिनेट, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा ।

(2) कुल-सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

लेखा
नियन्त्रक ।

31. (1) एक लेखा नियन्त्रक होगा जो विश्वविद्यालय का बजट और लेखा विवरणी तैयार करने और पेश करने सहित लेखा सम्बन्धी सभी मामलों के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(2) लेखा नियन्त्रक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

(3) लेखा नियन्त्रक,—

- (i) यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश के सिवाए ऐसा व्यय जो बजट में प्राधिकृत नहीं है, विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जाए; और
- (ii) किसी भी ऐसे व्यय को नामजूर कर देगा जो किन्हीं परिनियमों के निबन्धनों द्वारा अधिदिष्ट नहीं है या जिसके लिए परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है किन्तु ऐसा नहीं किया गया है ।

(4) विश्वविद्यालय का समस्त धन बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसूचित बैंक या सरकारी प्रतिभूतियों में रखा जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए “अनुसूचित बैंक” से ऐसा बैंक अभिप्रेत 1934 का 11 है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित है ।

32. (1) विश्वविद्यालय का सम्पदा अधिकारी, विश्वविद्यालय के भवनों, लानों, उद्यानों और अन्य सम्पत्ति की अभिरक्षा, अनुरक्षण और प्रबन्ध के लिए, कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा ।

सम्पदा
अधिकारी ।

(2) सम्पदा अधिकारी ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

33. (1) विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालयाध्यक्ष होगा जो पुस्तकालय से सम्बन्धित सभी विषयों के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा ।

पुस्तका-
लयाध्यक्ष ।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

34. (1) विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी कल्याण अधिकारी होगा जो विद्यार्थियों के कल्याण सम्बन्धी सभी विषयों के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा ।

विद्यार्थी
कल्याण
अधिकारी ।

(2) विद्यार्थी कल्याण अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

35. (क) (1) हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित संघटक महाविद्यालय होंगे :—

महा-
विद्यालय ।

- (i) कृषि महाविद्यालय, पालमपुर ;
 - (ii) पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान महाविद्यालय, पालमपुर; और
 - (iii) ऐसे अन्य महाविद्यालय जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए जाएं; और
- (ख) डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चर ऐण्ड फारैस्ट्री, सोलन के निम्नलिखित संघटक महाविद्यालय होंगे :—

- (i) हाटिकल्चर ऐण्ड फारैस्ट्री महाविद्यालय, सोलन; और

(ii) ऐसे अन्य महाविद्यालय जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए जाएं।

(2) प्रत्येक महाविद्यालय के अन्तर्गत ऐसे विभाग होंगे जो विहित किए जाएं और प्रत्येक विभाग को ऐसे पाठ्य विषय सौंपे जाएंगे जिन्हें विद्या परिषद् उचित समझे।

(3) प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष होगा जो निवासी शिक्षण के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति, अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए अनुसंधान निदेशक के प्रति और प्रसार शिक्षा के प्रयोजनों के लिए प्रसार शिक्षा निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा।

(4) प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष का चयन कुलपति द्वारा किया जाएगा और उस द्वारा बोर्ड के अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।

(5) विभागाध्यक्ष के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं।

अनुसंधान
प्रायोगिक
स्टेशन।

36. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित विश्वविद्यालय के विद्यमान प्रायोगिक स्टेशन या उप-स्टेशन या संस्थान, इस अधिनियम के अधीन निगमित तत्स्थानी विश्वविद्यालय के भाग होंगे और इस अधिनियम के अधीन निगमित विश्वविद्यालय, नए प्रायोगिक स्टेशन या उप-स्टेशन संस्थित या प्रारम्भ कर सकेगा या वर्तमान स्टेशनों का विस्तार कर सकेगा या उन्हें बन्द कर सकेगा।

(2) सरकार, प्रायोगिक स्टेशनों, उप-स्टेशनों, संस्थानों और सम्बद्ध विभागों की अनुसंधान परियोजनाओं को, उस तारीख से, जिसे सरकार अधिसूचना द्वारा विविष्टि करे, विश्वविद्यालय को अन्तरित कर सकेगी।

(3) सरकार को किसी भी प्रायोगिक स्टेशन, उप-स्टेशन और संस्थान को, एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय को अन्तरित करने और उन्हें इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय में विभाजित करने की शक्ति होगी।

अनुसंधान
प्रोग्राम।

37. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन रहते हुए, ग्रामीण जनता के हितों के लिए, इस अधिनियम के अधीन निगमित विश्वविद्यालय, इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (4) में इसके समक्ष उपदर्शित क्षेत्रों से सम्बन्धित, मुख्यतः निदेशित समस्याओं के बारे में अनुसंधान करेगा।

(2) विश्वविद्यालय उसे सौंपे गए क्षेत्रों में, अनुसंधान क्रियाकलापों पर नियन्त्रण के लिए अपने अनुसंधान संगठन के माध्यम से प्रधान अभिकरण होगा।

प्रसार
प्रोग्राम।

38. (1) विश्वविद्यालय प्रसार शिक्षा प्रोग्रामः—

(क) अनुसंधान के निष्कर्षों पर आधारित लाभकारी जानकारी कृषकों, फलोद्यानियों, किसानों और अन्य को उनकी सहायता और समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध कराएगा;

(ख) विद्यार्थियों, कृषकों, फलोद्यानियों और किसानों के लाभ के लिए प्रदर्शन और अध्यापन प्रोग्राम आयोजित करेगा; और

(ग) विश्वविद्यालय के अन्य कृत्यों और राज्य के अन्य समुचित अभिकरणों से समन्वय करेगा।

(2) विश्वविद्यालय, ग्रामीण उत्थान और पशुपालन, कृषि उत्पादन, फलों, सब्जियों और फार्म वानिकी के उत्पादन में वृद्धि के लिए, आवश्यक उन्नत पद्धति पर अनुसंधान परिणामों को, कृषकों, फलोद्यानियों, किसानों और अन्य में प्रसारित और प्रदर्शित करने के लिए, राज्य में आवश्यक प्रसार शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी होगा।

39. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों से भिन्न कर्मचारीवृन्द उसके बोर्ड के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और अध्यापकों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के परिनियमों के अधीन यथागठित चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा की जाएगी।

अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति।

(2) परिनियमों में अन्यथा उपबन्धित मामलों के सिवाए, विश्वविद्यालय का प्रत्येक वेतन-भोगी अधिकारी और अध्यापक लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों और सेवा की शर्तों से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियमों से अनसंगत होगी और ऐसी संविदा विश्वविद्यालय के कुलपति के पास रहेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी।

(3) जब तक कि अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित न हो, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित हो।

40. यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, अपील या किसी भी प्रकार की अन्य कार्यवाहियां लम्बित हों, तो वे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के कारण उपशमित या समाप्त नहीं होंगी या उनसे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां, इस अधिनियम के अधीन निगमित तत्स्थानी विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध जारी, अभियोजित या प्रवर्तित की जा सकेंगी।

विधिक कार्य-वाहियां।

41. विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी, अध्यापक या अन्य कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की आयु और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

सेवा निवृत्ति और सेवा की अन्य शर्तें।

42. (1) विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकीय कर्मचारीवृन्द और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधि गठित करेगा जो वह उचित समझे।

पेंशन और भविष्य निधि।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार गठित ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधि के लिए सरकार घोषणा कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध ऐसी निधि पर उसी रूप में लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो :

परन्तु विश्वविद्यालय को भविष्य निधि की रकम को ऐसी रीति में, जैसे वह अवधारित कर, विनिहित करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित या उसके द्वारा पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं के व्यक्ति ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन शासित होंगे जैसी कि विश्वविद्यालय और सरकार के बीच तय की जाएं।

विश्वविद्यालय और कर्मचारी-वृन्द के बीच विवाद के लिए माध्यस्थम् अधिकरण।

43. विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अध्यापक या कर्मचारी के बीच हुई संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक या कर्मचारी के अनुरोध पर, बोर्ड द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक से गठित माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा। अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और अधिकरण द्वारा निर्णीत मामलों के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकेगा। प्रत्येक ऐसा अनुरोध माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के अर्थों के अन्तर्गत इस धारा के निबन्धनों पर माध्यस्थम् को निवेदन समझा जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 2 को छोड़कर उसके सभी उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

1940 का 10

निधियाँ और अनुदान।

44. (1) साधारण निधि.—विश्वविद्यालय की एक साधारण निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा की जाएंगी :—

- (i) फीस, विन्यास, अनुदान और छात्रावास, प्रायोगिक स्टेशन और फार्मों सहित विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों से आय;
- (ii) अभिदाय या अनुदान जो सरकार द्वारा ऐसी शर्तों पर दिया जाएगा जैसी वह अधिरोपित करे;
- (iii) अनुदान, सदान और उपकृति; और
- (iv) अन्य प्राप्तियाँ।

(2) प्रतिष्ठापन निधि :—

- (i) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठापन निधि के नाम से एक निधि, राज्य सरकार द्वारा उस निधि में जमा करने के लिए अभिदायों और अनुदानों से और विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य राशियों से जो उक्त निधि में जमा की जा सकें, गठित करेगा।
- (ii) प्रतिष्ठापन निधि का धन, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के खण्ड (क) से (घ) तक में उल्लिखित या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में विनिहित किया जाएगा।
- (iii) विश्वविद्यालय, अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी अन्य राज्य सरकार या कानूनी निकाय और विन्यास से अनुदान या ऐसी शर्तों पर जैसी विश्वविद्यालय और अभिदाता या दाता के बीच तय हुई हों, दान लेने के लिए, सक्षम होगा।

1882 का 2

(3) निधियों का प्रबन्ध.—विश्वविद्यालय की साधारण निधि, प्रतिष्ठापन निधि और अन्य निधियों का प्रबन्ध ऐसे उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा अधिकृत की जाएँ।

(4) सरकारी अनुदान.—निधियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय को व्यपगत न होने वाला निम्नलिखित रूप में एकमुश्त अनुदान देगी :—

- (क) अनुदान जो कर्मचारीवृन्द के वेतन और भत्तों, आकस्मिक व्यय, पूर्ति और सेवाओं के अनुमानित कुल व्यय से कम न हो,

(ख) नई स्कीमों और प्रोग्रामों और कर्मचारीवृन्द को देय वेतनमान के पुनरीक्षण, वृद्धियों, मंहगाई और अन्य भत्तों में वृद्धि के कारण विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार आवर्ती और अनावर्ती व्यय की ऐसी अतिरिक्त मदों को पूरा करने के लिए अनुदान में वार्षिक वृद्धि।

45. (1) विश्वविद्यालय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जैसा कि राज्य सरकार निदेश दे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अपने क्रियाकलापों का सही और पूर्ण लेखा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।

वार्षिक
और लेखा
संपरीक्षा
रिपोर्ट।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं को, कुलपति के निदेश के अधीन लेखा नियंत्रक द्वारा तैयार किया जाएगा और विश्वविद्यालय द्वारा प्रोद्भूत या प्राप्त कुल धन लेखाओं में दर्ज किया जाएगा।

(3) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय का लेखा और तुलन-पत्र बोर्ड के माध्यम से सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा जो कि समय-समय पर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकरण से उनकी संपरीक्षा करवाएगी।

(4) संपरीक्षा किए जाने पर, लेखा मुद्रित किया जाएगा और कुलपति द्वारा संपरीक्षा-रिपोर्ट सहित बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा जो उक्त रिपोर्ट को उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसी टिप्पणियों के साथ, जैसी कि वह उचित समझे, राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा इसे ये रिपोर्ट देने के पश्चात् यथा शक्यशीघ्र, किन्तु उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के नौ मास के भीतर जिससे ये सम्बन्धित हो, इन रिपोर्टों को राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

46. इस अधिनियम के अन्यथा किसी अन्य विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखत में, विद्यमान विश्वविद्यालय से सम्बोधित निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन निगमित तत्स्थानी विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश है।

किसी वस्ता-
वेज इत्यादि
में विद्यमान
विश्वविद्या-
लय के संदर्भ
का
अर्थान्वयन।

47. यदि इस अधिनियम के अधीन निगमित विश्वविद्यालयों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसा विवाद प्रथमतः उक्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा निपटाया जाएगा और यदि ऐसे कुलपति किसी निश्चय पर पहुंचने में असफल रहते हैं तो विषय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम और आवद्ध कर होगा।

अन्तर
विश्व-
विद्यालय
विवाद।

48. विश्वविद्यालय का बोर्ड इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण को, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रयुक्त करने के लिए कर सकेगा, जैसी विहित की जाएं।

शक्तियों का
प्रत्यायोजन।

49. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और उस समय तक जब तक धारा 10 के मद 1, 4, 5 और 7 में उल्लिखित प्राधिकरण सम्यक् रूप में गठित नहीं किए जाते हैं, कुलपति, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, अस्थायी रूप से समितियां नियुक्त कर सकेगा जो इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे प्राधिकरण की शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, निष्पादन और पालन करेगी।

तदर्थ समिति
का गठन।

विश्व-विद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन के सम्बन्ध में विवाद । 50. यदि यह प्रश्न उठता हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधि-करण या निकाय के लिए सदस्य के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित या नामित या नियुक्त किया गया है या क्या वह सदस्य बनने का पात्र है या नहीं; तो यह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु कुलाधिपति ऐसे विनिश्चय से पूर्व उससे प्रभावित व्यक्ति/व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

अस्थाई उपबन्ध ।

51. (1) उप-धारा (2) में अन्तर्निष्ठ उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्यमान डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हाटिकल्चर ऐण्ड फारैस्ट्री, सोलन के फील्ड क्राप की शाखा में इसकी स्थापना से पूर्व उसमें प्रवेश प्राप्त स्नातकोत्तर विद्यार्थी अपनी उपाधियां हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकेंगे ।

(2) ऐसे समय तक, जब तक कि विद्यमान डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हाटिकल्चर ऐण्ड फारैस्ट्री, सोलन की (बी० एस० सी० हाटिकल्चर) में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों का प्रथम बैच उक्त उपाधि पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में प्रवेश नहीं कर जाता, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में पहले से नामांकित विद्यार्थियों द्वारा, प्रमाण-पत्रों, डिप्लोमाओं, उपाधियों, पदकों और अन्य विशिष्टताओं का हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त करना जारी रहेगा ।

कठिनाइयों का निराकरण ।

52. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेंगी जो इस अधिनियम के प्रयोजन से असंगत न हो और जो इन कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन प्रकाशित प्रत्येक आदेश, इसके प्रकाशन के पश्चात् राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी भी विधि न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा कि उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसका निराकरण किया जाना अपेक्षित नहीं था ।

परिणियम

53. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के परिणियम किसी भी विषय के लिए उपबन्ध कर सकेंगे और विशिष्टतः निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध करेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का चयन, नामनिर्देशन, नियुक्ति और पद पर बने रहना, जिसके अन्तर्गत इन प्राधिकरणों और अधिकारियों/अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की रिक्तियों का भरना और ऐसे अन्य सभी सम्बन्धित विषय हैं, जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय है ;

- (ग) अधिनियम के अधीन, नियुक्तियों के लिए बोर्ड की सिफारिश करने वाली कमिटी का गठन ;
- (घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियां और कर्तव्य ;
- (ङ) महाविद्यालयों में अध्यापन खण्ड/विभागों की स्थापना ;
- (च) कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया, परिलब्धियां और सेवा की शर्तें और उसकी शक्तियां ;
- (छ) अध्यापकों का वर्गीकरण और नियुक्ति की रीति ;
- (ज) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए उपदान या भविष्य निधि या दोनों की स्थापना ;
- (झ) उपाधियों और डिप्लोमाओं को संस्थित करना ;
- (ञ) सम्मानक उपाधियां प्रदान करना ;
- (ट) विभागों की स्थापना, समामेलन, उप-विभाजन और उत्पादन ;
- (ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की स्थापना और उत्पादन ;
- (ड) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित करना ;
- (ढ) स्नातकों का रजिस्टर रखना ;
- (ण) विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश और उनका नामांकन और उस रूप में उनका जारी रहना ;
- (त) विश्वविद्यालयों की उपाधियों और डिप्लोमाओं के लिए अधिकारित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ;
- (थ) वे शर्तें जिनके अधीन उपाधियों, डिप्लोमाओं या अन्य पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा और वह रीति जिसके अनुसार परीक्षाएं ली जाएंगी और उपाधियों और डिप्लोमाओं को प्रदान करने के लिए पात्रता ;
- (द) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों में निवास के लिए फीस का उपग्रहण ;
- (ध) ऐसे छात्रावासों की मान्यता और अधीक्षण जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित नहीं हैं ;
- (न) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की संख्या, अर्हताएं, परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें और उनकी सेवा और कार्यकलापों के अभिलेख तैयार करना और रखना ;
- (प) वह फीस जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित की जा सकेगी ;
- (फ) विश्वविद्यालय के कार्य में नियोजित व्यक्तियों को संदत्त किया जाने वाला पारिश्रमिक और भत्ते, जिनके अन्तर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं ;
- (ब) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों, वृत्तियों और फीस की रियायतों को प्रदान करने की शर्तें ;
- (भ) विश्वविद्यालयों द्वारा या उसकी ओर से की जाने वाली संबिदाओं या करारों के निष्पादन की रीति ; और
- (म) ऐसे सभी अन्य विषय जिनका इस अधिनियम के अधीन परिनियम द्वारा उपबन्ध दिया जाना है या किया जा सकेगा ।

परिनियम
बनाना।

54. (1) बोर्ड, समय-समय पर, इस धारा में इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से नवीन या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा और उन परिनियमों का संशोधन और निरसन कर सकेगा।

(2) विद्या परिषद् बोर्ड को परिनियम के प्रारूप का प्रस्ताव कर सकेगी और ऐसे प्रारूप पर बोर्ड की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा :

परन्तु विद्या परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम के किसी प्रारूप या परिनियम के संशोधन का प्रस्ताव तब तक नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान न किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गई राय पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

(3) बोर्ड किसी ऐसे प्रस्ताव पर, जैसा उप-धारा (2) में निर्दिष्ट है, विचार कर सकेगा और प्रस्तावित परिनियमों को पारित या अस्वीकृत कर सकेगा या विद्या परिषद् को ऐसे किसी संशोधन सहित, जिसका वह सुझाव दे, अंशतः या पूर्णतः पुनर्विचार के लिए वापिस भेज सकेगा।

(4) बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड को किसी परिनियम के प्रारूप का प्रस्ताव कर सकेगा और बोर्ड उस प्रस्ताव को स्वीकृत या यदि वह किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित है जो विद्या परिषद् के कार्यक्षेत्र में न आता हो, अस्वीकृत कर सकेगा।

(5) यदि ऐसा प्रारूप ऐसे विषय से सम्बन्धित है जो विद्या परिषद् के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो बोर्ड इसे विचार के लिए विद्या परिषद् को निर्दिष्ट करेगा जो बोर्ड को या तो ऐसी रिपोर्ट भेज सकेगी कि वह प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करती है, जो तब बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया गया समझा जाएगा या प्रारूप को बोर्ड के समक्ष ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा जैसे विद्या परिषद् अनुमोदित करे और ऐसे प्रस्तुत किए प्रारूप के सम्बन्ध में इस धारा के उपबन्ध उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे विद्या परिषद् द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत प्रस्तावित प्रारूप को लागू है।

(6) किसी नए परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या परिनियम के किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उसको अपनी अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधायित कर सकेगा या उसे बोर्ड को विचार के लिए भेज सकेगा।

(7) नए परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाले परिनियम को तब तक कोई विधिमन्यता नहीं होगी जब तक कि उसे कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता।

(8) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी परिनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

विनियम

55. (1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण निम्नलिखित के लिए इस अधिनियम और परिनियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा :—

(क) उसकी बैठकों में अनुमरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिस्थित करना ;

(ख) उन सभी विषयों के लिए उपबन्ध करना जो इस अधिनियम और परिनियमों के द्वारा विनियमों द्वारा विहित किए जाने हैं, और

(ग) उन अन्य विषयों के लिए उपबन्ध करना जो प्राधिकरण से ही सम्बन्धित हों और जिसके बारे में इस अधिनियम और परिणियमों द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को बैठक की तारीखों की और उन बैठकों में संव्यवहृत किए जाने वाले काम-काज की सूचना देने के लिए और बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने का उपबन्ध करने के लिए विनियम बनाएगा।

(3) विद्या परिषद्, परिणियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्बन्धित महाविद्यालयों/संकायों के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं की पद्धति और विश्व-विद्यालय की उपाधियों और डिप्लोमाओं के लिए विनियम बना सकेगी।

(4) विद्या परिषद्, महाविद्यालयों से प्रारूप प्राप्त करने के पश्चात् संकायों से प्राप्त हुए प्रारूप में परिवर्तन नहीं कर सकेगी, किन्तु उसे अस्वीकृत या विद्या परिषद् के सुझावों सहित महाविद्यालय/संकाय को और विचार के लिए भेज सकेगी।

(5) बोर्ड, ऐसी रीति में जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, इस धारा के अधीन बनाए गए किसी विनियम में संशोधन करने या उप-धारा (2) के अधीन किसी विनियम को रद्द करने के निर्देश जारी कर सकेगा।

56. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1978 और डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हाटिकल्चर ऐण्ड फारेस्ट्री सोलन अधिनियम, 1986 निरसित हो जाएंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उप-धारा (1) के अधीन निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी मानों कि यह अधिनियम उस दिन को प्रवृत्त हो गया था जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी।

निरसन और
व्यावृत्ति।

1978 का 3
1986 का 6

अनुसूची

[धारा 2(ट) 3, 4 और 36 देखें]

क्रमांक 1	विश्वविद्यालय का नाम 2	मुख्यालय 3	विषय 4
1.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	पालमपुर	कृषि
2.	डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हाटिकल्चर एण्ड फारेस्ट्री, सोलन।	नौनी (सोलन)	हाटिकल्चर एण्ड फारेस्ट्री।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य की आर्थिक-व्यवस्था को विकसित करने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1978 में, कृषि और सहवृद्ध विज्ञान के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। पश्चात्-वर्ती, पिछले वर्ष वन सम्पदा के परिरक्षण और विकास में वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीक अपना कर औद्योगिकी और वानिकी की समस्याओं का प्रभावकारी रूप से मुकाबला करने के लिए, कृषि प्रक्षेत्र (कम्प्लेक्स) सोलन को पूर्ण विश्वविद्यालय में बदल दिया गया है और उसका नाम हमारे प्रथम मुख्यमन्त्री महोदय के नाम पर रखा गया है, अर्थात् डाक्टर यशवन्त सिंह परमार युनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चर ऐण्ड फार्स्ट्री। इस समय ये दोनों विश्वविद्यालय अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश के उपर्युक्त विश्वविद्यालयों में कृषि, औद्योगिकी और वानिकी के क्षेत्रों में अध्यापन, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के एकरूपात्मक स्तरों को प्रवृत्त करने और वित्तीय व्यवस्था और कर्मचारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता रखने के लिए, उचित उपबन्ध करने की आवश्यकता महसूस की गई है। इसके अतिरिक्त, इन विश्वविद्यालयों को शासित करने के लिए एक ही अधिनियमित, केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त विश्वविद्यालयों को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता देने को भी सुकर करेगी।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है।

शिमला:

26 नवम्बर, 1986.

संत राम,
प्रभारी मंत्री।

वित्तीय जापन

यह विधेयक कृषि, औद्यानिकी और वानिकी के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा का एकरूपात्मक स्तर लागू करने और विद्यमान "हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय" और "डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चर ऐण्ड फारेस्ट्री, सोलन" की वित्तीय व्यवस्था में एकरूपता लाने के प्रयोजन के लिए और उक्त विश्वविद्यालयों के कार्यकल्पों को एक ही अधिनियम द्वारा विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया जा रहा है। विधेयक का खण्ड 3 उक्त दो विद्यमान विश्वविद्यालयों के लिए दो तत्स्थानी विश्वविद्यालय स्थापित करने का उपबन्ध करता है।

खण्ड 9 के अधीन इस विधायी अध्यापय के अधीन निगमित किए जाने वाले विश्वविद्यालयों के क्रिया-कलापों को समन्वित करने वाली एक शिक्षा और अनुसंधान परिषद् और खण्ड-11 के अधीन प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक सिनेट के अतिरिक्त नए विश्वविद्यालयों का संगठन लगभग वही होगा जो विद्यमान है।

सरकार ने इन दोनों विश्वविद्यालयों को चालू वित्तीय वर्ष में योजना और गैर-योजना स्कीमों के अधीन क्रमशः 235.15 लाख रुपए और 216.19 लाख रुपए की सहायता अनुदान का उपबन्ध किया है। प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 11 के अधीन प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए सिनेट और खण्ड 9 के अधीन समन्वय परिषद् के गठन पर उपगत होने वाले प्रति मास 10,000 रुपए व्यय के सिवाय कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वर्तित नहीं होगा। व्यय, सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई गई सहायता अनुदान में से पूरा किया जाएगा और विधेयक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय उपगत नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी जापन

विधेयक का खण्ड 52, सरकार को, दो वर्ष के भीतर कठिनाइयों के निराकरण के लिए आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करता है और इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक आदेश, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

खण्ड 54 में यह उपबन्ध किया गया है कि प्रबन्ध बोर्ड समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा और उक्त खण्ड में यथा विहित रीति से परिनियम को संशोधित या निरसित कर सकेगा। खण्ड 55 उस में प्रगणित विषयों की बाबत विनियम बनाने के लिए विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों को सशक्त करता है। प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[उद्घान विभाग फाईल सं० उद्घान-च (11) 2/86]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 1986 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जान के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरः स्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Bill, 1986 (1986 Ka Vidheyak Sankhyank 21) as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

Bill No. 21 of 1986.

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY BILL, 1986

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A BILL

to make suitable provisions for enforcing uniform standards of teaching, research and extension education in the fields of agriculture, horticulture and forestry in the two Universities of Himachal Pradesh namely the Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya at Palampur and Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry at Solan, as also, for having uniformity in financial arrangements and in service conditions of the employees in the said Universities.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Short title,
extent and
commence-
ment.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
- (b) "Act" means the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986;
- (c) "agriculture" means the basic and applied sciences of soil and water management, crop production, home science, food science, agricultural engineering and technology, animal husbandry including veterinary and dairy science, fisheries, mushroom growing, bee-keeping, tea cultivation, sericulture, vegetables, social sciences and agricultural marketing, processing, co-operation, land use and management and economic and social uplift of the rural people;
- (d) "authority" means any authority as specified in section 10 of this Act;
- (e) "Board" means the Board of Management of the University as constituted under section 12;
- (f) "Board of Studies" means the Board constituted under section 18 of the Act;
- (g) "Chancellor" means the Chancellor of the University;
- (h) "college" means a constituent college of the University under the direct control and management of the Board whether located at the headquarters, campus or elsewhere;

- (i) "Council for Education and Research" means the Himachal Pradesh Council of Agricultural, Horticultural and Forestry Education and Research, set up under section 9 of the Act;
- (j) "Dean" means the Dean of a college;
- (k) "existing University" means a University specified in column (2) of the Schedule to this Act;
- (l) "extension" means educational activities concerned with the training of orchardists, farmers and other groups serving agriculture, horticulture and forestry, in improved practices related thereto and the various phases of scientific technology related to agriculture, horticulture and forestry including post-harvest technology and marketing;
- (m) "faculty" means teaching, research and extension staff of a college or a department of the University, including all members of the staff having the rank of an Assistant Professor and above;
- (n) "forestry" means and includes basic and applied sciences concerning silviculture, plant breeding, farm forestry, conservation of ecology of the biosphere, wild life, sericulture, medicinal and aromatic plants and their products;
- (o) "Government" or "State Government" means Government of the State of Himachal Pradesh;
- (p) "Governor" means the Governor of the State of Himachal Pradesh;
- (q) "horticulture" means the basic and applied sciences of fruits, vegetables, floriculture plantation, crops, spices, hops and shall include mushroom growing, landscaping, bee-keeping, marketing and processing of horticultural produce;
- (r) "hostel" means a place of residence for students of the University maintained or recognised by the University either as a part of or separate from a college;
- (s) "officer" means an officer of the University as specified in section 22 of the Act;
- (t) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;
- (u) "prescribed" means prescribed by the Statutes and Regulations made under the Act;
- (v) "Regulations" means the rules and procedures established for the operation and functioning of the authorities as specified or deemed to have been specified in section 10 of the Act and may include the provisions made by the Academic Council relating to the establishment and maintenance of academic standards of the University as well as the provisions made by the competent authority of the University for the conduct of students, staff and other employees of the University and for conducting the routine business of the University and these may include provisions relating to the service conditions of employees;
- (w) "scheduled castes" means the scheduled castes specified in Part-VI of the Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and/or notified by the Government;
- (x) "scheduled tribes" means the scheduled tribes specified in Part-V of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 and/or notified by the Government;
- (y) "Statutes" means the Statutes of the University governing matters of policy and procedure as set forth in section 53 of the Act;

- (z) "student" means a person enrolled in the University for undergoing a course of studies in that University for obtaining a degree, diploma or other academic distinction duly instituted;
- (za) "teacher" means a person appointed under section 39 of the Act for the purpose of imparting instructions and/or conducting and guiding research and/or extension programme and may include any other person who may be declared by the Statutes to be a teacher on such terms and conditions as may be prescribed by the Board;
- (zb) "University" means the Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya, Palampur and/or Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan as incorporated or deemed to have been incorporated under this Act; and
- (zc) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University appointed under section 24 of this Act.

3. (1) On the commencement of this Act, in relation to each of the existing Universities specified in column (2) of the Schedule to this Act, the corresponding Universities shall be incorporated or deemed to have been incorporated under this Act as a successor body corporate with the same name and with perpetual succession and common seal and shall sue and be sued by the same name.

Incorporation of Universities.

(2) The members of the Board of Management, the Academic Council and other authorities of the existing University shall be deemed to have been appointed, elected, nominated or co-opted as such member of the corresponding authority of the University set up under this Act, and shall cease to be such members on expiry of the period of three months from the commencement of this Act or on the day on which the corresponding authorities of the University are constituted under this Act, whichever is earlier.

(3) Subject to the provisions to the contrary contained in this Act, the Chancellor, the Vice-Chancellor and other officers of the existing Universities, shall continue to hold their respective offices under the corresponding Universities incorporated under this Act.

(4) Each University shall be competent to acquire and hold property, both movable and immovable, by way of purchase, lease and exchange or otherwise, and to lease, sell or otherwise transfer or dispose of any movable or immovable property, which vests or may have become vested in or has been acquired by it, for the purpose of the University and to borrow money from the Central Government, State Government or from any body corporate approved by the State Government and to contract and do all things necessary for the purpose of this Act:

Provided that no immovable property of the University shall, except with the prior approval of the Government, be transferred by the Board of Management, by way of sale, lease, tenancy, mortgage or gift, nor shall any money be borrowed or advances taken on the security thereof.

(5) The place specified against each University in column (3) of Schedule to this Act shall be the headquarters of the University. of
by

Jurisdiction

4. (1) The territorial jurisdiction of the University set up under this Act shall extend to the entire State of Himachal Pradesh and the powers in respect of teaching, research and extension programme in the field of agriculture, horticulture and forestry shall be exercisable by each University to the extent indicated against it in column (4) of the Schedule to this Act.

(2) The University may, in its relative field, assume responsibility for the maintenance of training centres, research and experimental stations and for the programmes of training of field extension workers therein and for the establishment, development and operation of Polytechnics as may be required in various parts of the State.

(3) All colleges, research and experimental stations and other institutions coming under the jurisdiction and authority of the University shall be constituent units of the University under the full management and control of the University officers and authorities. No unit shall be recognised as an affiliated unit.

(4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no educational institution, situate within the State and run by the University other than the University incorporated under this Act, imparting instructions in the fields, assigned to it *vide* column (4) of the Schedule to this Act, for Bachelor's degree and above, shall be associated in any way with or be admitted to any privilege of any other University incorporated by law in India and such privilege granted by any other University to any educational institution within the State prior to the commencement of this Act shall be deemed to be withdrawn on such commencement.

(5) The University may have collaboration in research with any projects of any University having multi-disciplinary approach, Central and State institutions.

Objects

5. The University shall be deemed to be established and incorporated for the following purposes in respect of the subjects as indicated in column (4) of the Schedule to this Act, namely:—

- (1) making provision for imparting education in agriculture, horticulture, forestry and other allied branches of learning and scholarship which a University may find necessary to include;
- (2) furthering the advancement of learning and prosecution of research, both basic and applied;
- (3) undertaking extension of such sciences, specially to the rural people of the State; and
- (4) such other purposes as the University may from time to time determine.

Admission to the University.

6. (1) University shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, be open to all persons:

Provided that nothing in this section shall—

- (a) require a University to admit to any course of study any person who does not meet the prescribed academic standards for admission to or to retain on its rolls, persons whose academic records are below the minimum standard required for the award

of a degree or whose personal conduct is such as to be prejudicial to the purposes of the University or to the rights and privileges of other students and staff;

- (b) be deemed to require a University to admit to any course of study a larger number of students that can be accommodated in the teaching, research and extension programmes of the University or in any particular college or department as determined by the Academic Council.

(2) Subject to the foregoing provisions the University shall, according to a specific decision of the Board, reserve seats in colleges for socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and the scheduled tribes, provided that no such person shall be entitled to be admitted to the University, unless he fulfils the standards for admission laid down by the University in respect of such candidates.

7. The University shall, in the fields indicated against it in column (4) of the Schedule to this Act, have the following powers and functions, namely:—

Powers and functions of the University.

- (1) to provide for instructions and for the conduct of research and dissemination of the findings of research and technical information through an extension education programme;
- (2) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
- (3) to institute courses of study and hold examinations and confer degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on persons who have—
 - (a) pursued a course of study as prescribed; or
 - (b) carried out research in the University or an institution recognised in this behalf by the University under the conditions as may be prescribed;
- (4) to confer honorary degrees and other distinctions as may be prescribed;
- (5) to provide lectures and instructions for field workers, orchardists, farmers and other persons, not enrolled as regular students of the University and to grant certificates to them as may be prescribed;
- (6) to co-operate with other Universities and authorities in such manner and for such purposes as the University may determine, subject to the limitations set forth in section 4 of this Act;
- (7) to maintain colleges relating to the fields indicated against it in column (4) of the Schedule to this Act;
- (8) to maintain laboratories, libraries, research stations and institutions and museums for teaching, research and extension education in the fields indicated against it in column (4) of the Schedule to this Act;
- (9) to institute teaching, research and extension education posts required by the University and to make appointments thereto;
- (10) to create administrative, ministerial and other posts required by the University and to make appointments thereto;

- (11) to institute and award fellowships, scholarships and prizes in accordance with the Statutes;
- (12) to institute and maintain residential accommodation for students and staff of the University;
- (13) to fix demand and receive such fees and other charges as may be prescribed;
- (14) to supervise and control the residence, conduct and discipline of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and welfare;
- (15) to determine qualifications for teachers and to recognise persons as are qualified to give instructions in a college or to carry out research and extension education in the fields indicated against it in column (4) of the Schedule to this Act;
- (16) to do all such acts and things, whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be required in order to further the objects of the University.

Visitation
and inspection.

8. (1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection to be made by such person(s), as he may direct, of any University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments and any institution, college or hostel maintained or administered by the University and of the teaching and other work conducted by the University or under its auspices and of the conduct of any other function of the University, and to cause an inquiry to be made in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

(2) The Chancellor shall, in every case, give due notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(3) The Chancellor shall communicate to the University the result of such inspection or inquiry, and may, after ascertaining its opinion thereon, advise the University upon the action to be taken and fix a time-limit for taking such action.

(4) The University shall, within the time-limit so fixed, report to the Chancellor the action which has been taken or is proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.

(5) The Chancellor may, where action has not been taken by the University to the satisfaction of the Chancellor within the time-limit fixed and after considering any explanation furnished or representation made by the University, issue such directions as the Chancellor may deem fit and the University shall comply with such directions.

(6) Notwithstanding anything contained in the preceding sub-section of this section, if at any time the Chancellor is of the opinion that the affairs of the University are not managed in furtherance of the objects of the University or in accordance with the provisions of the Act and the statutory regulations or the special measures desirable to maintain the standards of teaching, examination, research or extension, he may indicate to the University any matter in regard to which he desires an explanation, and call upon the University to offer such explanation within such time as may be specified by the Chancellor. If the University fails to offer any explanation

within the time specified or offers an explanation which, in the opinion of the Chancellor is unsatisfactory, the Chancellor may issue such instructions as appear to him to be necessary and desirable in the circumstances of the case and may exercise such powers as he may consider necessary for giving effect to these instructions.

(7) The University shall furnish such information relating to the administration of the University as the Chancellor may require.

9. (1) For the purposes of effective co-ordination in the activities of the Universities set up in this State under this Act, particularly in relation to teaching, research, Extension education and other matters of common interest and also for having periodical evaluation of the functioning of and for supervision over the Universities and their academic and financial activities and programmes, the State Government shall constitute a Council for Education and Research to be called "The Himachal Pradesh Council of Agricultural, Horticultural and Forestry Education and Research".

Constitution of State Council for Education and Research, its powers and duties.

(2) The Chief Secretary to the State Government shall be the Chairman of the Council and the Council shall have the following members, namely:—

- (i) the Agricultural Production Commissioner to the State Government;
- (ii) the Vice-Chancellors of the Universities;
- (iii) the Secretaries to the State Government in the Departments of Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Finance and Forest; and
- (iv) one representative of the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

(3) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Council for Education and Research shall have the following powers and functions, namely:—

- (a) to grant permission to the Universities for starting any new courses or disciplines, departments, schemes or projects to be financed out of the State exchequer by way of grants/loans;
- (b) to review, from time to time, the work done in the Universities relating to education, teaching, research and Extension education in agriculture, horticulture and forestry with a view to achieving effective co-ordination in the activities of the Universities and to give them suitable guidance and directions;
- (c) to advise the State Government on matters relating to activities of the Universities, which may be referred to it by the State Government;
- (d) to exercise such other powers and to discharge such other functions as are incidental or requisite to give effect to the provisions of this Act;
- (e) to take decisions in relation to transfer/division of research experimental stations from one University to the other.

(4) The Council for Education and Research, in the exercise of its powers and the discharge of its functions, shall have the power to issue necessary

directions to the Universities under intimation to the Chancellor which shall be final and binding on the Universities and it shall be the duty of the Vice-Chancellor concerned to ensure that such directions are promptly and properly implemented and for this purpose the Vice-Chancellor shall have and exercise all the necessary powers as provided in sub-section (5) of section 25 of this Act.

(5) The Council for Education and Research shall, in conducting its business, determine such procedure as it may deem fit.

(6) The Council for Education and Research shall have the power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof or any defect in the constitution thereof.

Authorities

10. The following shall be the authorities of the University, namely:—

- (i) the Senate;
- (ii) the Board of Management;
- (iii) the Academic Council;
- (iv) the Extension Council;
- (v) the Research Council;
- (vi) the Board of Studies;
- (vii) the Finance Committee; and
- (viii) such other bodies of the University as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

Senate.

11. (1) The Senate shall consist of the following members in respect of:—

(A) THE HIMACHAL PRADESH KRISHI VISHVA VIDYALAYA

Ex-officio Members:

- (i) Chancellor;
- (ii) Vice-Chancellor;
- (iii) Agricultural Production Commissioner to the Government;
- (iv) Secretary (Agriculture) to the Government;
- (v) Secretary (Animal Husbandry) to the Government;
- (vi) Heads of Government Departments of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries;
- (vii) all Deans and Directors and other statutory officers of the University ;

Other Members:

- (viii) two members to be elected by and from amongst the Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly in such manner as may be prescribed by the Speaker of the Assembly;
- (ix) two teachers/Heads of Departments of the University other than Deans/Directors having at least 5 years' teaching experience to be elected in the manner prescribed in the Statutes so as to give representation to the constituent colleges of the University;
- (x) one representative of the employees of the University (other than teachers) to be elected in the manner prescribed in the Statutes;

(B) DR. YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY, SOLAN

Ex-officio Members:

- (i) Chancellor;
- (ii) Vice-Chancellor;
- (iii) Agricultural Production Commissioner to the Government;
- (iv) Secretary (Horticulture) to the Government;
- (v) Secretary (Forest) to the Government;
- (vi) Heads of Government Departments of Agriculture, Horticulture and Forests;
- (vii) all Deans and Directors and other statutory officers of the University;

Other Members:

- (viii) two members to be elected by and from amongst the Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly in such manner as may be prescribed by the Speaker of the Assembly;
- (ix) two teachers/Heads of the Departments of the University other than Deans/Directors, having at least 5 years' teaching experience to be elected in the manner prescribed in the Statutes so as to give representation to the constituent colleges of the University;
- (x) one representative of the employees of the University (other than teachers) to be elected in the manner prescribed in the Statutes.

(2) The term of office of the members of the Senate, other than *ex-officio* members, shall be for a period of two years with effect from the dates of their respective elections and shall include any further period which may intervene between the expiration of the said period of two years and the date of the next succeeding election or nomination as the case may be, not being an election or nomination to fill up a casual vacancy.

(3) The Senate shall, on the dates to be fixed by the Chancellor, meet once in a calendar year and this meeting shall be called the annual meeting of the Senate.

(4) The Chancellor may, whenever he deems fit, and shall upon a requisition in writing signed by not less than one-third of the total number of members of the Senate convene a special meeting of the Senate.

(5) Subject to the provisions of this Act, the Senate shall—

- (i) review the broad policies and programmes of the University and suggest measures for the improvement and development of the University;
- (ii) consider and pass resolution on the annual report, annual accounts, financial estimates and audit report on such accounts of the University; and
- (iii) advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice.

12. (1) The Chancellor shall constitute a Board of Management for the University and the Board shall consist of the following in respect of—

Board of Management.

(A) HIMACHAL PRADESH KRISHI VISHVA VIDYALAYA

Ex-officio Members:

- (i) Vice-Chancellor;
- (ii) Vice-Chancellor of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan;
- (iii) Agricultural Production Commissioner to the Government;
- (iv) Secretary (Agriculture) to the Government;
- (v) Secretary (Animal Husbandry) to the Government;
- (vi) Secretary (Finance) to the Government;
- (vii) Heads of the Government Departments of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries;

Other Members:

- (viii) one officer to be nominated by the Chancellor from amongst Deans/Directors of the University;
- (ix) two eminent scientists with a background of research and education, one in agriculture and the other in animal husbandry science to be nominated by the Chancellor;
- (x) two progressive agriculturists, farmers or animal breeders to be nominated by the Chancellor;
- (xi) one progressive agriculturist/animal breeder from the tribal areas of the State to be nominated by the Chancellor;
- (xii) one outstanding woman social worker preferably having background of rural advancement, to be nominated by the Chancellor;
- (xiii) one distinguished industrialist or manufacturer having special knowledge in agricultural development to be nominated by the Chancellor;
- (xiv) one distinguished engineer to be nominated by the Chancellor;
- (xv) one representative of the Indian Council for Agricultural Research; and
- (xvi) one representative of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun (to be set up).

(B) DR. YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY, SOLAN

Ex-officio Members:

- (i) Vice-Chancellor;
- (ii) Vice-Chancellor of Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya;
- (iii) Agricultural Production Commissioner to the Government;
- (iv) Secretary (Horticulture) to the Government;
- (v) Secretary (Finance) to the Government;
- (vi) Secretary (Forests) to the Government;
- (vii) Heads of Government Departments of Horticulture, Forest and Agriculture;

Other Members:

- (viii) one officer to be nominated by the Chancellor from amongst the Deans/Directors of the University;

- (ix) two eminent scientists, one in horticulture and the other in forestry, to be nominated by the Chancellor;
- (x) two progressive orchardists or farmers to be nominated by the Chancellor;
- (xi) one progressive orchardist/farmer from the tribal areas of the State, to be nominated by the Chancellor;
- (xii) one outstanding woman social worker, preferably having background of rural advancement to be nominated by the Chancellor;
- (xiii) one distinguished engineer to be nominated by the Chancellor;
- (xiv) one representative of the Indian Council for Agricultural Research, New Delhi; and
- (xv) one representative of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun (to be set up).

(2) The Registrar shall be the non-member Secretary of the Board of the University.

(3) The term of the members, except the *ex-officio* members, of the Board shall be for a period of two years.

(4) A member of the Board may resign his office by a notice, in writing, addressed to the Chancellor of the University.

(5) If, for any reason, a vacancy occurs in the office of a non-official member of the Board, the same may be filled by appointing or nominating, as the case may be, another person thereto for the un-expired term, in accordance with the provisions of this section.

(6) Eight members of the Board shall form a quorum for a meeting of the Board.

(7) The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Board.

(8) The members of the Board shall not be entitled to receive any remuneration for the performance of their functions as such members under this Act except such daily and travelling allowances as may be prescribed.

13. (1) The Board shall exercise and perform the following powers and functions, namely:—

Powers and functions of the Board.

- (a) to review and consider the financial requirements and estimates for the University and approve its budget;
- (b) to make appointments to the posts in accordance with the provisions of the Act;
- (c) to provide for the administration of any funds placed at the disposal of the University for the purposes intended;
- (d) to arrange for the investment and withdrawal of funds of the University;
- (e) to borrow money for capital improvements and make suitable arrangements for its repayment;
- (f) to provide for accepting, acquiring, holding and disposing of property on behalf of the University;
- (g) to direct the form and use of the common seal of the University;
- (h) to appoint such committees, either standing or temporary, as the Board may consider necessary, and establish the terms of reference thereof within the purview of the Act or the Statutes;
- (i) to determine and regulate policies relating to the University in accordance with this Act or the Statutes;

- (j) to make financial provision for instructions, teaching and training in such branches of learning and courses of study as determined by the Academic Council within the purposes of this Act and for research and advancement and dissemination of knowledge;
- (k) to provide for the establishment and maintenance of colleges, hostels, laboratories, experimental farms and other facilities necessary for carrying out the purposes of this Act;
- (l) to make provision for instituting and conferring degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
- (m) to provide for institution, maintenance and award of scholarships, fellowships, studentships, medals, prizes, etc;
- (n) to accept, on behalf of the University, trusts, bequests and donations;
- (o) to meet at such times and in such places, as often as it may deem necessary:

Provided that a regular meeting of the Board shall be held at least once in every three months; and

- (p) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with the Act and the Statutes and to exercise such powers and to discharge such duties as may be conferred on or imposed upon the Board by this Act or Statutes.

(2) The Board may, for purposes of consultation, invite any person having experience in or special knowledge of any subject under consideration to attend a meeting. Such a person may speak in and otherwise take part in the proceedings of such meeting but shall not be entitled to vote at any such meeting. Any person so invited shall be entitled to such allowances for attending the meeting, as may be prescribed.

The Academic Council

14. (1) There shall be an Academic Council for the University which shall, subject to the provisions of the Act and the Statutes, superintend, direct and control and be responsible for the maintenance of standards of instructions, education and examinations and other matters connected with the conferment of degrees or award of diplomas and certificates and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by the Statutes. It shall advise the Vice-Chancellor on all academic matters of the University.

(2) The Academic Council shall consist of the following members, namely:—

- (i) Vice-Chancellor, who shall be the *ex-officio* Chairman;
- (ii) Deans of Colleges of the University;
- (iii) Director of Research of the University;
- (iv) Director of Extension Education of the University;
- (v) Director (Forestry Education), Forest Research Institute, Dehradun;
- (vi) Librarian of the University;
- (vii) Student's Welfare Officer of the University;

(viii) two senior-most professors from each college for a term of two years, by rotation;

(ix) in respect of—

(a) Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya, two eminent scientists, one in agriculture and the other in animal sciences;

(b) Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, two eminent scientists, one in horticulture and the other in forestry; and

(x) Registrar shall be the *ex-officio* Secretary of the Academic Council.

(3) One-third of the number of members of the Academic Council shall form a quorum.

15. (1) The Academic Council shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, have the power to regulate and prescribe all courses of study and determine curricula and shall have general control of teaching and other educational programmes within the University and shall be responsible for the maintenance of standards thereof.

Powers and functions of the Academic Council.

(2) It shall have power to make Regulations consistent with this Act and the Statutes relating to all academic matters subject to its control and to amend or repeal such Regulations.

(3) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Academic Council shall have power to—

(i) advise the Board on all academic matters including the control and management of libraries;

(ii) make recommendations for the establishment of new colleges, departments, experimental stations, sub-stations, professorships, associate professorships and other teaching posts including posts in research and extension education and in regard to the duties thereof;

(iii) formulate, modify or revise schemes for the constitution or reconstitution of departments of teaching, research and Extension education;

(iv) make Regulations regarding the admission of students to the University, and determine the number of students to be admitted;

(v) make Regulations relating to the courses of study leading to degrees, diplomas and certificates;

(vi) make Regulations relating to the conduct of examinations and maintain and promote standards;

(vii) make recommendations regarding post-graduate teaching, research and extension education;

(viii) make recommendations regarding the qualifications to be prescribed for teachers in the University;

(ix) recommend to the Board the conferment of honorary degrees; and

(x) exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under the provisions of this Act.

Extension
Council.

16. (1) There shall be an Extension Council for the University.

(2) The constitution, powers and functions of the Extension Council shall be such as may be prescribed by the Statutes.

Research
Council.

17. (1) There shall be a Research Council for the University.

(2) The constitution, powers and functions of the Research Council shall be such as may be prescribed by the Statutes.

Board of
Studies.

18. (1) There shall be a Board of Studies for each college of the University.

(2) The Deans of colleges shall be the Chairmen of the respective Boards of Studies and Heads of the Departments of the colleges shall be the members thereof.

(3) The Vice-Chancellor may nominate on the Board of Studies such other teachers of related subjects or sciences from the same or other colleges, as he may deem fit.

(4) The duties of such Board of Studies shall be to prescribe syllabi so as to ensure integrated and well balanced courses of studies and other related matters concerning academics.

(5) Each department of the college shall have a Head whose appointment, powers and duties shall be such as may be prescribed by the Statute and who shall be responsible to the Dean of the college for the proper organisation and working of the department and shall be responsible to the Directors of Research and Extension Education, respectively for the research and extension education entrusted to his department.

(6) The Board of Studies shall perform such functions or discharge such duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.

Finance
Committee,
its powers
and duties.

19. (1) There shall be a Finance Committee for the University, consisting of—

(i) Vice-Chancellor, who shall also be the *ex-officio* Chairman of the Committee;

(ii) Finance Secretary to the Government or his representative;

(iii) Heads of Government Departments of Horticulture and Forests in case of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan and of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries in case of the Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya; and

(iv) one member chosen by the Board from amongst its non-official members.

(2) The Comptroller shall be the non-member Secretary of the Finance Committee.

(3) The Finance Committee shall have the following powers, namely:—

- (i) to examine the annual accounts of the University and to advise the Board thereon;
- (ii) to examine the annual budget estimates and to advise the Board thereon;
- (iii) to examine the annual audit report and action taken thereon;
- (iv) to review the financial position of the University from time to time;
- (v) to make recommendations to the University on all matters relating to the finances of the University; and
- (vi) to make recommendations to the Board on all proposals involving expenditure for which no provision has been made in the budget or which involves expenditure in excess of the amount provided in the budget.

20. (1) Save as otherwise provided in this Act, if any member other than *ex-officio* members of any authority or other body of a University is unable, by reason of his death, resignation, removal or otherwise to complete his full term of office, the vacancy so caused, shall, as soon as convenient, be filled by the appointment, election or nomination, as the case may be, and the person so appointed, elected or nominated, shall fill such vacancy for the unexpired portion of the term for which the member, in whose place such person is appointed, elected or nominated, would otherwise have continued in office.

Provisions in relation to membership of authorities.

(2) The Chancellor, on the recommendation of the Board, may remove any person from the membership of any authority of the University on the ground that such person has been convicted of an offence involving moral turpitude:

Provided that no order for removal shall be passed against any person without giving him an opportunity of being heard.

(3) A person who is a member of any authority of the University as a representative of another body, whether of the University or not, shall cease to be a member of such authority if, before the expiry of the term of his membership, he ceases to be a member of that other body by which he was appointed or elected.

(4) Wherever any person becomes a member of any authority of the University by virtue of the office held by him, he shall forthwith cease to be a member of such authority if he ceases to hold such office before the expiry of the term of his membership:

Provided that he shall not be deemed to have ceased to hold his office merely by reason of his proceeding on leave for a period not exceeding four months.

(5) Any member, other than *ex-officio* members, of any authority of the University may resign his office by a letter addressed to the Registrar for being placed before the appropriate authority.

(6) Any officer of the University, whether salaried or otherwise, other than the Dean or the Director, may resign his office by a letter addressed

to the Vice-Chancellor and such resignation shall take effect from the date on which the same is accepted by the authority competent to fill the vacancy or on the expiry of three months from the date of receipt by the Vice-Chancellor, whichever is earlier.

Validity and protection of certain acts.

21. (1) No act or proceeding of any authority or other body of the University shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy among its members or by reason of such person having taken part in the proceeding who is subsequently found not to have been entitled to do so.

(2) Save as otherwise provided in this Act, all acts and orders in good faith done and passed by the University or any of its authorities shall be final and no suit shall be instituted against or damages claimed from the University or its authority for anything done or purported to have been done in pursuance of this Act or the Statutes or the Regulations.

(3) No suit prosecution or other proceedings shall lie against any officer or other employee of the University for any act done or purported to have been done under this Act or the Statutes or the Regulations without the previous sanction of the Board.

(4) No officer or other employee of the University shall be liable in respect of any such act in a civil or criminal proceeding if the act was done in good faith in the course of the execution of his duties or in discharge of the functions imposed on him by or under this Act.

Officers of the University.

22. The following may be the officers of the University, namely:—

- (i) Chancellor;
- (ii) Vice-Chancellor;
- (iii) Deans of Colleges;
- (iv) Director of Research;
- (v) Director of Extension Education;
- (vi) Registrar;
- (vii) Comptroller;
- (viii) Estate Officer;
- (ix) Librarian;
- (x) Students' Welfare Officer; and
- (xi) such other persons in the service of the University as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

Chancellor.

23. (1) The Governor shall, by virtue of his office, be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University and shall, when present, preside at any Convocation of the University.

(3) Every proposal to confer an honorary degree shall be subject to the confirmation by the Chancellor.

(4) The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on him by this Act or the Statutes.

24. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University, who shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the Selection Committee consisting of—

Vice-Chancellor.

- (i) a nominee of the Chancellor;
- (ii) the Director General, Indian Council of Agricultural Research; and
- (iii) the Chairman, Universities Grants Commission or his nominee.

(2) The Chancellor shall nominate one of the members referred to in sub-section (1) as the Chairman of the Selection Committee.

(3) The Vice-Chancellor shall normally hold office for a term of five years and be eligible for re-appointment for another five years but not beyond the age of 65. The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed and shall not be varied to his disadvantage after his appointment:

Provided that the Chancellor may allow him to continue in office until his successor is appointed but this period shall not exceed one year.

(4) The Vice-Chancellor may resign by giving a notice of one month in writing under his signatures addressed to the Chancellor. The Chancellor may waive off the period of notice and accept the resignation forthwith in consultation with the State Government.

(5) During temporary absence of the Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any other cause, the Chancellor may make such arrangements for carrying out the duties of the Vice-Chancellor, as he may deem fit, from amongst the senior faculty members of the University. Where the post of the Vice-Chancellor falls permanently vacant either by resignation or otherwise, the vacancy shall be filled in accordance with the provisions of sub-section (1) of this section and the Vice-Chancellor so appointed shall hold office for a full term or till the attainment of the age of 65 years, whichever is earlier.

(6) If, in the opinion of the Chancellor, a Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him or if it appears to the Chancellor that the continuance of that Vice-Chancellor in office is detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, by order, remove the Vice-Chancellor, after giving him an opportunity to show cause against the action proposed to be taken against him.

25. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and *ex-officio* Chairman of the Board and the Academic Council. He shall, in the absence of the Chancellor, preside over the Convocation of the University and confer degrees on the persons entitled to receive them.

Powers and duties of Vice-Chancellor.

(2) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for due maintenance of discipline and order in the University.

(3) The Vice-Chancellor shall convene meetings of the Board of Management and the Academic Council unless he temporarily delegates the power to some other officer of the University.

(4) The Vice-Chancellor shall ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Regulations and he shall exercise such powers as may be necessary in that behalf.

(5) The Vice-Chancellor shall be responsible for prompt and proper implementation on the part of the University and its authorities and officers, of the directions by the Council for Education and Research under section 9, from time to time, and shall have and exercise all the powers necessary for this purpose, notwithstanding anything contained in this Act or in the Statutes and the Regulations made or deemed to have been made under this Act.

(6) The Vice-Chancellor shall be responsible for the presentation of the annual financial estimates and the annual accounts and balance-sheet to the Board.

(7) The Vice-Chancellor may take any action in any emergency which in his opinion calls for immediate action and shall, in such a case and as soon as may be thereafter, report his action to the authority which would ordinarily have dealt with the matter and if the authority disagrees with the action of the Vice-Chancellor the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final:

Provided that nothing in this section shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.

(8) Subject to the provisions of the preceding sub-section, the Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Board regarding the appointment, suspension and dismissal of officers, teachers and other employees of the University.

(9) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (6) affects any person in the service of the University to his disadvantage, such action shall not be taken unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard and the person against whom any action is proposed to be taken may prefer an appeal to the Board within thirty days of the date on which the action proposed to be taken is communicated to him.

(10) The Vice-Chancellor shall be responsible for the proper administration of the University and for a close co-ordination and integration of teaching, research and extension education.

(11) The Vice-Chancellor may appoint temporarily, under intimation to the Board, a suitable person for a period not exceeding six months in the vacancy of an officer, teacher or any other employee in the University.

(12) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers, as may be prescribed, for carrying out the purposes and provisions of this Act.

(13) The Vice-Chancellor shall, at the close of each academic year, in the manner prescribed in the Statutes, assess and evaluate the teaching, extension and research work done by the members of the faculty. On such assessment or evaluation, if the Vice-Chancellor is of the opinion that the work and conduct of any member of the faculty is not satisfactory, he shall in the manner laid down in the Statutes, initiate or cause to be initiated action against such a member.

26. (1) An officer of the University, referred to in clauses (iii) to (xi) of section 22 shall be a whole time officer of the University and shall be appointed by the Board on the recommendations of the Selection Committee, as may be constituted for the purpose under the Statutes.

Other officers of the University and their general terms and conditions.

(2) The salary and allowances and other conditions of service of such an officer shall be such as may be prescribed by the Statutes.

27. (1) Each college shall have a Dean who shall be responsible to the Vice-Chancellor for all matters concerning his college.

Deans of colleges.

(2) The Dean shall also be responsible for the organisation and the conduct of the resident instructions of the departments of his college.

(3) The Dean shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed upon him by the Statutes.

28. (1) There shall be a Director of Research who shall be responsible to the Vice-Chancellor of the University for the direction and co-ordination of research programmes in the fields concerned as set forth in section 37 of this Act, and efficient working of the research stations.

Director of Research.

(2) The Director of Research shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on him by the Statutes.

29. (1) There shall be a Director of Extension Education who shall be responsible to the Vice-Chancellor of the University for extension programmes in the fields concerned as set forth in section 38 of this Act.

Director of Extension Education.

(2) The Director of Extension Education shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on him by the Statutes.

30. (1) There shall be a Registrar in the University who shall be responsible to the Vice-Chancellor of the University and shall be the *ex-officio* Secretary of the Senate, Board of Management and Academic Council of the University.

Registrar.

(2) The Registrar shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed upon him by the Statutes.

31. (1) There shall be a Comptroller who shall be responsible to the Vice-Chancellor of the University for all matters pertaining to the accounts of the University including the preparation and presentation of the budget and statement of accounts.

Comptroller.

(2) The Comptroller shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed upon him by the Statutes.

(3) The Comptroller shall—

- (i) ensure that expenditure not authorised in the budget is not incurred by the University except by way of investment; and
- (ii) disallow any expenditure not warranted by the terms of any Statutes or for which provision is required to be made by the Statutes but has not been so made.

(4) All moneys belonging to the University shall be kept in a Scheduled Bank and/or Government securities approved by the Board.

Explanation.—For the purposes of this sub-section “Scheduled Bank” means a Bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934.

11 of 1934

Estate Officer.

32. (1) The Estate Officer of the University shall be responsible to the Vice-Chancellor for the custody, maintenance and management of the buildings, lawns, gardens and other properties of the University.

(2) The Estate Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed upon him by the Statutes.

Librarian

33. (1) There shall be a Librarian in the University who shall be responsible to the Vice-Chancellor for all matters concerning the library.

(2) The Librarian shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed upon him by the Statutes.

Students' Welfare Officer.

34. (1) There shall be a Students' Welfare Officer in the University who shall be responsible to the Vice-Chancellor for all matters connected with the students' welfare.

(2) The Students' Welfare Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed upon him by the Statutes.

Colleges.

35. (1) The following shall be the constituent colleges:—

(a) in respect of the Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya—

- (i) the College of Agriculture, Palampur,
- (ii) the College of Veterinary and Animal Sciences, Palampur, and
- (iii) such other colleges as may be established by the University after the commencement of this Act, and

(b) in respect of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan—

- (i) the College of Horticulture and Forestry, Solan, and
- (ii) such other colleges as may be established by the University after the commencement of this Act.

(2) Every college shall comprise of such departments as may be prescribed and each department shall be assigned such subjects of study as the Academic Council may deem fit.

(3) There shall be a Head of each department who shall be responsible to the Dean for resident instructions to the Director of Research for the purposes of research and to the Director of Extension Education for the purposes of extension education.

(4) The Head of each department shall be selected by the Vice-Chancellor and appointed by him with the approval of the Board.

(5) The duties, powers and functions of Heads of departments shall be such as may be prescribed.

36. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the existing experimental stations/sub-stations and institutions of the University, mentioned in column (2) of the Schedule to the Act, shall form part of the corresponding University incorporated under this Act and the University incorporated under this Act may institute/start new experimental stations, sub-stations or expand or give up the existing ones.

Experimental stations for research.

(2) The Government may transfer to the University experimental stations, sub-stations, institutions and research schemes of the related departments from such date as the Government may by notification specify.

(3) The State Government shall have the power to transfer any experimental station, sub-station and institution from one University to another or to distribute them amongst the Universities set up under this Act.

37. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the University incorporated under this Act for the benefit of the rural population of the State, shall carry on research directed primarily to the problems connected with the fields indicated against it in column (4) of the Schedule to this Act.

Research programmes

(2) The University, through its research organisation, shall be the principal agency of control over research activities in the fields assigned to it.

38. (1) The extension education programmes of the University shall—

Extension programmes

- (a) make useful information based upon the findings of research available to agriculturists, orchardists, farmers and others to help and solve their problems;
- (b) conduct demonstration and teaching programmes for the benefit of students, agriculturists, orchardists and farmers; and
- (c) co-ordinate other functions of the University and other appropriate agencies of the State.

(2) The University shall be responsible for the extension education activities in the State necessary to disseminate and demonstrate to agriculturists, orchardists, farmers and others the findings of research on improved practices essential for rural uplift and to increase production on animal husbandry, agricultural products, fruits, vegetables and farm forestry.

Appointment of teachers, officers & staff.

39. (1) Subject to the provisions of this Act, the members of the staff other than teachers of the University, shall be appointed by the Vice-Chancellor or of the University with the approval of its Board and the teachers shall be appointed by the Board on the recommendations of such Selection Committees as may be constituted under the Statutes of the University.

(2) Except in cases otherwise provided for in the Statutes, every salaried officer and teacher of the University shall be appointed under a written contract which shall not be inconsistent with the provisions of this Act and the Statutes of the University for the time being in force in relation to the conditions of service and such contract shall be kept with the Vice-Chancellor of the University and a copy thereof shall be furnished to the officer or teacher concerned.

(3) The procedure for selection of officers, teachers and other employees of the University, unless otherwise provided in the Act, shall be as prescribed by the Statutes.

Legal proceedings.

40. If at the commencement of this Act any suit, appeal or other proceedings of whatever nature, are pending by or against the existing University, the same shall not abate, be discontinued or be in any way prejudicially affected by reasons of the coming into force of this Act, but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted or enforced by or against the corresponding University incorporated under this Act.

Retirement and other conditions of service.

41. The age of retirement and other conditions of service of every officer, teacher or other employee of the University shall be such as may be prescribed.

Pension and provident fund.

42. (1) The University shall constitute for the benefit of its officers, teachers, clerical staff and other employees in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed, such pension, insurance and provident fund as it may deem fit.

(2) For such pension, insurance and provident fund so constituted by the University, the Government may declare that provisions of the Provident Fund Act, 1925 shall apply to such fund as if it were a Government provident fund:

19 of 1925

Provided that the University shall have power to invest the provident fund amount in such manner as it may determine.

(3) Persons in Government service transferred to or re-employed by the University, shall be governed under such terms and conditions as may be agreed to between the University and the Government.

Tribunal of arbitration for dispute between University and staff.

43. Any dispute arising out of a contract between the University and any officer or teacher or employee of the University shall, on the request of the officer or teacher or employee concerned, be referred to a tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Board, one member nominated by the employee concerned and an umpire appointed by the Chancellor. The decision of the tribunal shall be final and no suit shall lie in any civil court in respect of the matters decided by the tribunal. Every such request shall be deemed to be a submission to arbitration upon the terms of this

10 of 1940

section within the meaning of the Arbitration Act, 1940 and all the provisions of the said Act, with the exception of section 2, thereof shall apply accordingly.

44. (1) *General Fund*.—The University shall have a General Fund to which shall be credited—

Funds and grants.

- (i) income from fees, endowments, grants and from properties of the University including hostels, experimental stations and farms;
- (ii) contribution or grants which shall be made by the Government on such conditions as it may impose;
- (iii) grants, donations and benefactions; and
- (iv) other receipts.

(2) *Foundation Fund*.—

- (i) the University shall form a fund called the Foundation Fund from contribution and grants made by the State Government for being credited to that fund and such other sums from the University which may be credited to the said fund;
- (ii) the money in the Foundation Fund shall be invested in the securities mentioned or referred to in clauses (a) to (d) of section 20 of the Indian Trusts Act, 1882;
- (iii) it shall be competent for the University in furtherance of its objectives, to accept grants from any State Government or statutory body and endowments or donations under such conditions as may be agreed upon between the University and the grantor or donor.

2 of 1882

(3) *Management of Funds*.—The General Fund, Foundation Fund and other funds of the University shall be managed according to such provisions as may be laid down by the Statutes.

(4) *Government Grants*.—Subject to availability of funds, the State Government shall every year make non-lapsable lump sum grants to the University as follows:—

- (a) a grant not less than the estimated net expenditure of pay and allowances of the staff, contingencies, supplies and services of the University; and
- (b) an annual increase in grant to meet such additional items of expenditure, recurring and non-recurring, as per requirements of the University, on account of new schemes and programmes, revision of pay scales, increments, increase in dearness and other allowances payable to the staff.

45. (1) The University shall prepare once in every financial year in such form and at such time as may be directed by the State Government an annual report giving a true and full account of its activities during the previous financial year.

Annual and audit reports.

(2) The annual accounts of the University shall be prepared by the Comptroller under the direction of the Vice-Chancellor and all the money accruing to or received by the University shall be entered in the accounts.

(3) The accounts and the balance sheet of the University shall be submitted by the Vice-Chancellor through the Board to the Government which shall cause them to be audited by an agency specifically authorised in this behalf by the State Government from time to time.

(4) The accounts, when audited, shall be printed and copies thereof, together with audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board, which shall forward the said audit report along with the annual report prepared under sub-section (1), immediately after the close of each financial year to the Government with such comments as it may deem fit and the Government shall as soon as may be after these reports are furnished by the University to it, but within a period of nine months after the close of the financial year to which these reports pertain, cause such reports to be laid before the State Legislative Assembly.

Construction of reference to existing University in any document etc.

46. Any reference to the existing University in any law, other than this Act, or in any contract or other instrument shall be construed as a reference to the corresponding University set up under this Act.

Inter-University disputes.

47. If any dispute arises between the Universities incorporated under this Act such dispute shall be resolved in the first instance by the Vice-Chancellors of the said Universities and in the event of failure of the Vice-Chancellors to arrive at an agreed solution with regard to any such dispute, the matter shall be referred to the Government and its decision thereon shall be final and binding.

Delegation of powers.

48. The Board of the University may delegate to any officer or authority of the University any of the powers conferred on it by this Act or by the Statutes to be exercised subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.

Constitution of ad-hoc committees.

49. Notwithstanding anything contained in this Act and until such time as the authorities mentioned in items (i), (iv), (v) and (vii) of section 10 are duly constituted, the Vice-Chancellor may, subject to the prior approval of the Chancellor, appoint committees temporarily to exercise, perform and discharge any of the powers, functions and duties of such authorities under this Act.

Disputes as to constitution of University authorities and bodies.

50. If any question arises as to whether any person has been duly elected, nominated or appointed or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided that before taking any such decision, the Chancellor shall give the person or persons affected thereby a reasonable opportunity of being heard.

Transitory provisions.

51. (1) Subject to the provisions contained in sub-section (2), the post-graduate students of the existing Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, enrolled before its establishment in the discipline of 'field crops' may obtain the degrees etc. from the Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya.

(2) Till such time as the first batch of students of the B.Sc. (Horticulture) admitted by the existing Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan enters the final year of that degree course, the students of the said University enrolled earlier in the Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya shall continue to receive certificates, diplomas, degrees, medals and other distinctions from the Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya.

52. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government, may by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the purposes of this Act as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Removal of difficulties.

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order published under this section shall, as soon as may be after its publication, be laid before the State Legislature.

(3) No order made under sub-section (1) shall be called into question in any court of law on the ground that no difficulty as is referred to in the said sub-section existed or was required to be removed.

53. Subject to the provisions of this Act, the Statutes of the University may provide for any matter and shall, in particular, provide for the following matters, namely:—

Statutes.

- (a) the constitution, powers and duties of the authorities of the University;
- (b) the selection, nomination, appointment and continuance in office of the members of the authorities of the University and of the officers, teachers and other employees of the University, including the filling up of vacancies and all other matters relating to these authorities and officers, teachers and other employees for which it may be necessary or desirable to provide;
- (c) the constitution of the Selection Committee for making recommendations to the Board for appointments under this Act;
- (d) the designation, the manner of appointment, powers and duties of the officers of the University;
- (e) establishment of divisions/departments of teaching in the colleges;
- (f) procedure of appointment, emoluments and conditions of service of the Vice-Chancellor and his powers;
- (g) the classification and the manner of appointment of teachers;
- (h) the constitution of gratuity or provident fund or both for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;
- (i) the institution of degrees and diplomas;
- (j) the conferment of honorary degrees;
- (k) the establishment, amalgamation, sub-division and abolition of departments;

- (l) the establishment and abolition of hostels maintained by the University;
- (m) the institution of fellowships, scholarships, medals and prizes;
- (n) the maintenance of a register of graduates;
- (o) the admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;
- (p) the courses of study to be laid down for degrees and diplomas of the University;
- (q) the conditions under which students shall be admitted to the degrees, diplomas or other courses and the manner in which the examinations are to be held and the eligibility for the award of degrees and diplomas;
- (r) the conditions of residence of the students of the University and the levy of fees for residence in hostels maintained by the University;
- (s) the recognition and supervision of hostels not maintained by the University;
- (t) the number, qualifications, emoluments and other conditions of service of officers, teachers and other employees of the University and the preparation and maintenance of record of their services and activities;
- (u) the fees which may be charged by the University;
- (v) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to persons employed for the business of the University;
- (w) the conditions for the award of fellowships, scholarships, medals, prizes, stipends and fee concessions;
- (x) mode of execution of contracts or agreements by or on behalf of the University; and
- (y) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Statutes.

Statutes
how made.

54. (1) The Board may, from time to time, make new or additional Statutes and may amend or repeal the Statutes in the manner hereinafter provided in this section.

(2) The Academic Council may propose to the Board the draft of a Statute and such draft shall be considered by the Board at its next meeting:

Provided that the Academic Council shall not propose the draft of any Statute or any amendments of a Statute affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity to express its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be considered by the Board.

(3) The Board may consider any such draft as is referred to in sub-section (2) and pass the proposed Statute or reject or return it to the Academic Council for re-consideration, either in whole or in part, together with any amendment which it may suggest.

(4) Any member of the Board may propose to the Board the draft of any Statute and the Board may either accept or reject the proposal if it relates to a matter not falling within the purview of the Academic Council.

(5) In case such a draft relates to a matter within the purview of the Academic Council, the Board shall refer it for consideration to the Academic Council which may either report to the Board that it does not approve the proposal, which, then, shall be deemed to have been rejected by the Board or submit the draft to the Board in such form as the Academic Council may approve, and the provisions of this section shall apply in the case of a draft so submitted as they apply in the case of a draft proposed to the Board by the Academic Council.

(6) A new Statute or additions to the Statute or any amendment or repeal of a Statute shall require the approval of the Chancellor who may accord his assent thereto or with-hold his assent or return the same to the Board for consideration.

(7) A new Statute or Statute amending or repealing an existing Statute shall have no validity unless it has been assented to by the Chancellor.

(8) All Statutes made under this Act shall be published in the Official Gazette.

55. (1) Any authority of a University may make Regulations consistent with this Act and the Statutes for—

Regulations.

(a) laying down the procedure to be observed at its meetings and the number of members required to form a quorum;

(b) providing for all matters which by this Act or the Statutes are to be provided for by the Regulation; and

(c) providing for any other matter(s) solely concerning the authority and not provided for by this Act and the Statutes.

(2) Every authority of the University shall make Regulations providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be transacted at the meetings and for keeping, of records of the proceedings of the meetings.

(3) The Academic Council may, subject to the provisions of the Statutes, make regulations providing for courses of study, system of examinations and degrees and diplomas of the University, after receiving drafts of the same from the college/faculty concerned.

(4) The Academic Council may not alter a draft received from the college/faculty but may reject or return it to the college/faculty for further consideration together with the suggestions of the Academic Council.

(5) The Board may, in such manner as it may specify, direct the amendment of any Regulation made under this section or the annulment of any Regulation made under sub-section (2).

Repeal and
saving.

56. (1) On the commencement of this Act, the Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya Act, 1978 and Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan Act, 1986 shall stand repealed. 30 of 1978
6 of 1986

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Act repealed under sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if this Act had come into force on the day on which such thing was done or action taken.

SCHEDULE

[See Sections 2 (k) 3, 4 and 36]

Sr. No. 1	Name of the University 2	Headquarters 3	Subjects 4
1.	The Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya	Palampur	Agriculture
2.	The Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan.	Nauni (Solan)	Horticulture and Forestry.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to develop the economy of the State and boost agricultural production, the Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya was set up in the year 1978 for the development of agriculture and allied sciences. Subsequently, in the last year, to tackle the problems of horticulture and forestry effectively by adopting scientific and modern techniques in the preservation and development of forest wealth the Agricultural Complex at Solan had been converted into a fullfledged University known after the name of our first Chief Minister, viz. Dr. Yashwant Singh Parmar University, of Horticulture and Forestry. At present, both these Universities are functioning in there respective fields. Now it has been felt necessary to make suitable provisions for enforcing uniform standards of teaching, research and extension education in the fields of agriculture, horticulture and forestry and for having uniformity in financial arrangements and in the service conditions of the employees of the said Universities of Himachal Pradesh. A part from this, the common enactment governing these Universities, will also facilitate recognition of the said Universities by the University Grant Commission for obtaining central assistance.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

SHIMLA :
The.....1986.

SANT RAM,
Minister-in-charge.

FINANCIAL MEMORANDUM

For enforcing uniform standards of teaching, research and Extension education in the fields of agriculture, horticulture and forestry and for having uniformity in financial matters in the existing Universities of the Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya and the Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, the Bill aims at the enactment of one single Act for regulating affairs of the said Universities. Clause 3 of the Bill provides for the establishment of two corresponding Universities in place of the aforesaid two existing Universities. The set-up under the new Universities will almost be the same as exists at present, excepting that under Clause 9 there will be a Council for Education and Research to co-ordinate the activities of the Universities being incorporated under this legislative measure and under Clause 11, each of the said Universities will have a Senate.

Both these Universities are provided grants-in-aid by the State Government under plan and non-plan schemes to the tune of Rs. 235.15 lakhs and 216.19 lakhs in the current financial year. No additional expenditure will be involved except to the tune of Rs. 10,000/- per annum for each University on account of the creation of a Senate for each University under Clause II and a co-ordination Council under Clause 9 of the proposed Bill. The expenditure will be met by the University out of the existing grants-in-aid provided to them by the State Government and no new additional expenditure will be incurred for implementation of the provisions contained in the Bill out of the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 52 of the Bill authorises the State Government to issue orders for the removal of difficulties within a period of two year and every order so issued shall be published in the Official Gazette and be laid before the State Legislature.

Clause 54 provides that the Board of Management shall, from time to time, make new or additional Statutes and may amend or repeal the Statute in the manner prescribed in the said Clause. Clause 55 empowers the authorities of the Universities to make Regulations in respect of the matters enumerated therein. These delegations are necessary and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[File No. Udyan-Cha (11) 2/86]

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Bill, 1986, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill by the Legislative Assembly.